रजिस्टर्ड सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1974/फाल्गुन 11, 1895
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1974/PHALGUNA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974

का०आ० 543—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 16-खादुर साहिब निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अजीत सिंह, सुपुत्र हरनाम सिंह, ग्राम व पो० आ० नागोके अमृतसर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अजीत सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि०स०/16/72(24)]

वी० नागसुब्रह्मण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1974

S.O. 543.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ajit Singh Son of Shri Harnam Singh, Village and Post Office Nagoke, District Amritsar (Punjab), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Punjab Legislative Assembly from 16-Khadoor Sahib constituency, has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ajit Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/16/72(24)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

का० आ० 544.--एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दार्जिलिंग टी एण्ड चिनकोना एसोसियेशन, लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 340/1970 दिनांक 26-10-1970) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 2/13/73—एम. 2]

का० म० शर्मा, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 19th February, 1974

S.O. 544.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. DARJEELING TEA AND CHINCHONA ASSOCIATION LIMITED under the said Act (Certificate of Registration No. 340/70 dated the 26th October, 1970).

[No. 2/13/73-M (II)]

K. M. SHARMA, Jt. Director, Inspection

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

का० आ० 545.--सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना सं० 12011/7/73 रा० प्र० सर्वे 1 दिनांक 7 नवम्बर, 1973 के पैरा 2 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 8(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन करने के लिये नियुक्त समिति 1973-74 के लिए 28 फरवरी, 1974 और 1974-75 के लिए 30 अप्रैल, 1974 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2. इस विभाग की अधिसूचना सं० एम-12011/7/73 रा० प्र० सर्वे०-1 दिनांक 2 फरवरी, 1974 इसके साथ ही निरसित की जाती है।

[सं० एम-12011/7/73 एन० एस० एस० आई०]

स० कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 16th February, 1974

S.O. 545. -In partial modification of para 2 of the Department of Statistics Notification No. M. 12011/7/73-NSS. I dated the 7th November, 1973, the Committee appointed in exercise of the powers conferred by Section 8(1) of the Indian Statistical Institute Act, 1959, shall submit its report for 1973-74 by the 28th February, 1974 and for 1974-75 by the 30th April, 1974.

2. This Department's Notification No. M-12011/7/73-NSS. I dated the 2nd January, 1974 is hereby cancelled.

[No. M-12011/7/73-NSS. I]

H. L. KOHLI, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1974

का० आ० 546.--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एल० वी० सिंह, आई० पी० एस० (बिहार-1955) को इसी समय से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी में पदेन-उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ई-17017/14/73 प्रशा० 1/पर्स० 2]

पी० के० जी० काइमल, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th February, 1974

S.O. 546.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Central Industrial Security Force Act, 1968, the Central Government appoints Shri L. V. Singh, IPS (Bihar—1955) as Ex-officio Deputy Inspector General Central Industrial Security Force, Bokaro Steel Limited, Bokaro Steel City, with immediate effect.

[No. E-17017/14/73-Ad. I/CISF/Pers. II]

P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1974

स्टाम्प

का०आ० 547.--केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस शुल्क से, जो तमिल नाडु जल प्रदाय और जल निकासी बोर्ड, मद्रास द्वारा 1972-73 के दौरान जारी किए जाने वाले छह करोड़ रुपये मूल्य के डिबेंचरों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, छूट देती है।

[सं० 4/74-स्टाम्प/फा०सं० 471/1/74-सी०शु० 7]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1974

STAMPS

S.O. 547.--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the debentures of the value of six crores of rupees to be floated by the Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board, Madras, during 1972-73, are chargeable under the said Act.

[No. 4/74-Stamps/F. No. 471/1/74-Cus. VII]

आदेश

का०आ० 548.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स कामानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०, मुम्बई, के पक्ष में जारी किए गए आस्थगित संदाय निर्यात संविदाओं से संबंधित वचनपत्रों और विनियमपत्रों को, उक्त वचनपत्रों और विनियमपत्रों की वास्तविक अवधि को विचार में लाए बिना, तारीख के पश्चात् या दर्शनोपरांत तीन मास से अधिक के लिए किंतु छह मास से अधिक के लिए नहीं, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य उतने स्टाम्प शुल्क से, जितना वचनपत्रों और विनियमपत्रों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से जब मांग से अन्यथा संदेय हो, अधिक हो, छूट देती है।

[सं० 5/74-स्टाम्प/फा०सं० 471/82/73-सी०शु० 7]

ORDER

S.O. 548.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby exempts the Promissory Notes and Bills of Exchange relating to deferred payment export contracts, issued in favour of M/s. Kamani Engineering Corporation Ltd., Bombay, from so much of stamp duty chargeable thereon under the said Act as is in excess of that leviable on Promissory Notes and bills of Exchange when payable otherwise than on demand for a period of more than three months but not more than six months after date or sight, irrespective of the actual period of the said Promissory Notes and Bills of Exchange.

[No. 5/74-Stamps/F. No. 471/82/73-Cus. VII]

आदेश

का०आ० 549.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस शुल्क से, जो तमिल नाडु आवास बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1972 में जारी किए गए एक सौ दस लाख रुपयों के मूल्य के स्टाक प्रमाणपत्रों और वचनपत्रों के रूप में डिबेंचरों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, छूट देती है।

[सं० 6/73-स्टांप/फा० सं० 471/73-सी० शु० 7]

ORDER

S.O. 549.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the debentures in the form of stock certificates and promissory notes to the value of one hundred and ten lacs of rupees, floated during December, 1972 by the Tamil Nadu Housing Board, are chargeable under the said Act.

[No. 6/74-Stamps/F. No. 471/81/73-Cus. VII]

आदेश

का०आ० 550.—भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो गुजरात राज्य वित्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले एक सौ पचास लाख रुपये मूल्य के बंध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, छूट देती है।

[सं० 7/74-स्टा०/फा० सं० 471/6/74-सी०शु० - 7]

ORDER

S.O. 550.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds to the value of one hundred and fifty lakhs of rupees, to be issued by the Gujarat State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 7/74-Stamps/F. No. 471/6/74-Cus. VII]

आदेश

का० आ० 551.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, मद्रास द्वारा जारी किए जाने वाले नव करोड़ और नब्बे लाख रुपये मूल्य के वचनपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, छूट देती है।

[सं० 8/74-स्टाम्प/फा० सं० 471/5/74-सीमा शुल्क 7]

जे० रामकृष्णन, अवर सचिव,

ORDER

S.O. 551.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the promissory notes to the value of nine crores and ninty lakhs of rupees, to be issued by the Tamil Nadu Electricity Board, Madras, are chargeable under the said Act.

[No. 8/74-Stamps/F. No. 471/5/74-Cus. VII]

J. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

का०आ० 552.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी संस्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी हैं और जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त संपदा अधिकारी, उक्त नियम की, या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई संपत्तियों की बाबत उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

क्रम० सं०	अधिकारी का पद नाम	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	उप मंडलीय प्रबंधक, उत्तरी मंडलीय कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम लक्ष्मी बीमा भवन, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका समिति और दिल्ली नगर निगम की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र।
2.	उप मंडलीय प्रबंधक, पश्चिमी मंडलीय कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन केन्द्र, जमशेदजी टाटा रोड़, मुम्बई-20	मुम्बई नगर निगम अधिनियम (1888 का मुम्बई अधिनियम 3) की धारा 3 के खंड (क 1) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई में समाविष्ट क्षेत्र।

1	2	3
3	मंडलीय सचिव, पूर्वी मंडलीय कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान बिल्डिंग, चित्तरंजन एवेन्यु, कलकत्ता-13	कलकत्ता, हावड़ा, बरानागोर, (24 परगना), हुगली-चिनसुराह, पनीहाटी, बैरकपुर, (24 परगना), बेहाला (24 परगना) और जिला नाडिया तथा जिला मिदनापुर की नगरपालिक सीमाओं के भीतर के क्षेत्र
4.	उप-मंडलीय प्रबंधक, दक्षिणी मंडलीय कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, माउंट रोड, मद्रास-2	मद्रास सिटी नगर निगम अधिनियम, 1919 (1919 का तमिल नाडु अधिनियम 4) और तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 (1920 का तमिल नाडु अधिनियम 5) की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र ।
5.	उप-मंडलीय प्रबंधक, केन्द्रीय मंडलीय कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, 16/98, महात्मा गांधी रोड, कानपुर ।	नगर महापालिका, कानपुर और छावनी बोर्ड, कानपुर की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र ।

[97 (54)–बीमा 2/72]

बी० एन० बागची, अवर सचिव

New Delhi, the 16th February, 1974

S.O. 552.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below, being officers of the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) and being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act and the said estate officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction, specified in column (3) of the said Table, in respect of the properties belonging to, or taken on lease by or on behalf of the said Corporation.

TABLE

Sl. No.	Designation of the officer	Local limits of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Deputy Zonal Manager, Northern Zonal Office, Life Insurance Corporation of India, Lakshmi Insurance Building, Asaf Ali Road, New Delhi.	Areas within the limits of the New Delhi Municipal Committee and the Municipal Corporation of Delhi.
2.	Deputy Zonal Manager Western Zonal Office, Life Insurance Corporation of India, Jeevan Kendra, Jamshedji Tata Road, Bombay-20.	Areas comprising Greater Bombay as defined in clause (a 1) of section 3 of the Bombay Municipal Corporation Act (Bombay Act 3 of 1888).
3.	Zonal Secretary, Eastern Zonal Office, Life Insurance Corporation of India Hindusthan Building, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13.	Areas within the municipal limits of Calcutta, Howrah, Baranagore, (24 Parganas), Hooghly-Chinsurah, Panihati, Barrackpur (24 Parganas), Behala (24 Parganas) and District Nadia and District Midnapur.
4.	Deputy Zonal Manager, Southern Zonal Office, Life Insurance Corporation of India, Mount Road, Madras-2.	Areas within the jurisdiction of the Madras City Municipal Corporation Act, 1919 (Tamil Nadu Act 4 of 1919) and the Tamil Nadu District Municipalities Act, 1920, (Tamil Nadu Act 5 of 1920)
5.	Deputy Zonal Manager, Central Zonal Office, Life Insurance Corporation of India, 16/98, Mahatma Gandhi Road, Kanpur.	Areas within the limits of the Nagar Mahapalika, Kanpur and the Cantonment Board, Kanpur.

[No. 97(54)-Ins.II/72]

B. N. BAGCHI, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1974

निर्देश : सं० फा० 9-4 (32)/72-बी ओ.-1 (जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का०आ० 553.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के अनुसरण में, भारतीय, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी, 1974 को प्रारंभ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1.	श्री एस०बी० गोदीवाला, विधि अधिकारी, मुख्य कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इंडिया, मुम्बई ।	खंड 3 के उपखंड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं ।
2.	श्री के० एच० पारीख, प्रबंध निदेशक, भारत औपथालमिक ग्लास लि०, दुर्गापुर-10 (पश्चिमी बंगाल राज्य) ।	खंड 3 के उपखंड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
3.	श्री राधाकांत रमाकांत उपासनी, प्रधानाचार्य, कृषि विद्यालय, वाराणसी ।	खंड 3 के उपखंड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
4	श्री मोहम्मद जिलानी, मेसर्स हाजी शेख इमाम साहिब एण्ड संस, नागेल्लामुडि, गुन्टूर, (आन्ध्र प्रदेश राज्य) ।	खंड 3 के उपखंड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
5.	श्री पी० के० सदानन्दन, लघु उद्योगपति, कोचीन ।	खंड 3 के उपखंड (च) के अनुसरण में—

[सं० 9-4/49/73-बी०ओ०-1-10]

(Department of Banking)

New Delhi, 7th February, 1974

Ref : No. F. 9-4(32)/72-BOI-(Vol. III)-4 dated the 4th December, 1972.

S.O. 553.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to

be the Directors of Union Bank of India, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975 :—

1. Shri S.B. Godiwalla, Law Officer, Head Office, Union Bank of India, Bombay.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri K. H. Parikh, Managing Director, Bharat Opthalmic Glass Ltd., Durgapur-10 (West Bengal State).	Representing the interests of depositors of the said Bank—in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri Radhakant Ramakant Upasani, Principal, Agricultural School, Varanasi.	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Mohamed Jeelani, M/s. Haji Sheikh Imam Sahib & Sons, Tangellamudi, Eluru, (Andhra Pradesh State).	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri P.K. Sadanandan, Small Scale Industrialist, Cochin.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. 9-4/49/73-B.O. I-10]

निर्देश: सं०फा० 9-4 (32)/72-बी०ओ०-1 (जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1974

का०आ० 554.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ करने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इलाहाबाद बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री जे० डी० जैन, महायक अधिकारी (श्रेणी 3), इलाहाबाद बैंक, मेरठ छावनी शाखा, मेरठ ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में — उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं है ।
2. श्री एम० आर० राय, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमी बंगाल वित्तीय निगम, कलकत्ता ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में — उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
3. श्री समर पाल सिंह, कुन्देश्वरी, जिला नैनीताल (उ०प्र०)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में — कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
4. श्री अब्दुल कयूम अंसारी, भदोही (उ०प्र०)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में — कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
5. डा० एम० ए० जहीर, सहप्राचार्य, कारबार प्रशासन, स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला । 6. श्री पद्मा लाल सोनकर, कानपुर (उ०प्र०) ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—

[सं०फा० 9-1/49/73-बी०ओ०-1 11]

Ref. No. F. 9-4(32)/72-BO. I (Vol. III)-4 dated the 4th December, 1972.

S.O. 554.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Allahabad Bank, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975:—

1. Shri J.D. Jain, Asstt. Officer (Grade III), Allahabad Bank, Meerut Cantt. Branch, Meerut.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri M. R. Roy, Managing Director, West Bengal Financial Corporation, Calcutta.	Representing the interests of depositors of the said Bank —in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri Samar Pal Singh, Kundeshwari, District Nainital (U.P.)	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Abdul Qayum Ansari, Bhadohi (U.P.)	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Dr. M. A. Zaheer, Associate Professor of Business Administration, Centre for Post Graduate Studies, Himachal Pradesh University, Simla. 6. Shri Panna Lal Sonker, Kanpur (U.P.)	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. F. 9-4/49/73-BO. I-11]

निर्देश: सं०फा० 9-4 (32)-बी०ओ० 1-(जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972.

का०आ० 555.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री के० वी० बालासुब्रमणियन, लेखापाल, अमीनजी कवाई शाखा, इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं है ।
2. श्री एस० के० राजू, महाप्रबन्धक, इण्डियन फिल्टर्स लि०, मद्रास ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
3. श्री टी० एन० पलानीस्वामी, "मुरुगनाथम", टुडियालूर जिला कोयम्बटूर, (तमिल नाडु)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
4. श्रीमती प्रभामयी देवी, कटक, उड़ीसा ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।

5. श्री जोसेफ चाकोला, व्यवसायी और उद्योगपति, कोचीन (केरल राज्य)।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—
6. श्री एन० बी० प्रसाद, इंजीनियर, हैदराबाद	

[स० 9-4/49/73-बी०ओ०-1-14]

Ref: No. F. 9-4 (32)-BOI-(Vol. III)-4 dated the 4th December, 1972.

S.O. 555.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Indian Overseas Bank, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975 :—

1. Shri K.V. Balasubramanian, Accountant, Aminji Kavai Branch, Indian Overseas Bank, Madras.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen-in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri M.K. Raju, General Manager, India Pistons, Ltd., Madras.	Representing the interests of depositors of the said Bank-in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri T.N. Palaniswamy, "Muruganatham", Tudiyalur, Distt. Coimbatore, (Tamil Nadu).	Representing the interests of farmers-in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Smt. Prabhamayi Devi, Cuttack, Orissa.	Representing the interests of artisans-in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri Joseph Chackola, Businessman and Industrialist, Cochin (Kerala State).	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.
6. Shri N. B. Prasad, Engineer, Hyderabad.	

[No. 9-4/49/73-BO. 1-14]

निर्देश : सं० फा० 9-4(32)/72-बी० ओ०-1 (जिल्द 3)-4 तारीख 4 दिसम्बर, 1972।

का० आ० 556.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देना बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री टी० एच० नारायणस्वामी, शाखा प्रबन्धक, शेयर बाजार शाखा, देना बैंक, फोर्ट, मुम्बई।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में— उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं है।
2. श्री कृष्ण राज, सम्पादक ईकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल वीकली, मुम्बई।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
3. श्री देव भाई प्रभुभाई पटेल, ग्राम पीपल गभन, जिला बुलसर, (गुजरात)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
4. श्री कृष्ण गोपाल मालवीय, इंदौर।	खण्ड 3 उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
5. श्री मोहिन्दर पाल पुरी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट नई दिल्ली।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—
6. प्रो० एम०बी० वनमाली, मुम्बई।	

[सं०फा० 9-4/49/73-बी०ओ०-1-8]

Ref. : No. F. 9-4(32)/72-BO. I (Vol. III)-4, dated the 4th December, 1972.

S.O.556.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Dena Bank, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975:—

1. Shri T. H. Narayanaswami, Branch Manager, Share Bazar Branch, Dena Bank, Fort, Bombay.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri Krishna Raj, Editor, Economic and Political Weekly, Bombay.	Representing the interests of depositors of the said Bank —in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri Devabhai Prabhubhai Patel, Village Pipal Gabhan, Distt. Bulsar, (Gujarat).	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Krishna Gopal Malviya, Indore.	Representing the interests of artisans-in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri Mohinder Pal Puri, Chartered Accountant, New Delhi,	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.
6. Prof. M.B. Vanamali, Bombay.	

[No. F. 9-4/49/73-BO. I-8]

निर्देश : सं० फा० 9-4(32)/72-बी० ओ०-1 (जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का० आ० 557.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री प्रभु रंजन सेन, अधिकारी, विदेश विभाग, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया कलकत्ता।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं।
2. श्री के० पी० बरुआ, प्रबन्ध निदेशक, असम राज्य वित्तीय निगम, शिलांग।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
3. श्री किनफाम सिंह, अनसोहसून, शिलांग।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।

4. श्री कार्तिक चन्द्र पाल, धुर्नी, जिला नादिया, (पश्चिमी बंगाल राज्य)।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
5. श्री एस० के० चौधरी, जेल रोड, अगरतला, त्रिपुरा।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—
6. श्री पी०सी० मिसाव, इम्फाल, मणिपुर।	

[सं० फा० 9-4/49/73-बी० ओ०-1-7]

Ref : No. F. 9-4(32)/72-BOI-(Vol.III)-4 Dated the 4th December 1972

S.O. 557.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of United Bank of India, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975:—

1. Shri Prabhu Ranjan Sen, Officer, Foreign Department, United Bank of India, Calcutta.	Representing the employees of the said Bank who are not workman—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri K. P. Barua, Managing Director, Assam State Financial Corporation, Shillong.	Representing the interests of depositors of the said Bank—in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri Kynpham Singh, Unsohsun, Shillong	Representing the interests of farmers—in pursuance of Sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Kartik Chandra Paul, Ghurni, Distt. Nadia (West Bengal State).	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri S. K. Choudhury, Jail Road, Agartala, Tripura.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.
6. Shri P. C. Misao, Imphal, Manipur.	

[No. F. 9-4/49/73-/BOI-7]

निर्देश : सं०फा० 9-4(32)/72-बी०ओ० 1(जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का० आ० 558.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कनारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री वी० पी० कामथ, बैंक-कार्यालय, मुम्बई में प्रबंधक, मुम्बई।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं।
2. डा० एच० नरसिम्हय्या, उपकुलपति बंगलोर विश्वविद्यालय, बंगलोर ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
3. श्री पी० एस० राजागोपाल नायडू, वेलोर, जिला उत्तरी आरकोट, (तमिलनाडु राज्य)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
4. मीर शौकत अली मास्टर शिल्पकार, मैसूर	खंड 3 के उपखंड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
5. श्री एस० आर० ठाकुर पणजी, गोवा ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—

[सं० 9-4/49/73-बी०ओ०-1-6]

Ref : No. F. 9-4 (32)/72 BOI (Vol. III) 4 Dated the 4th December 1972

S.O. 558.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Canara Bank, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975:—

1. Shri V. P. Kamath, Manager in the Bank's Office at Bombay, Bombay.	Representing the employess of the said Bank who are not workmen—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Dr. H. Narasimhayya, Vice Chancellor of Bangalore, University, Bangalore.	Representing the interests of depositors of the said Bank—in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri P.S. Rajagopal Naidu, Vellore, District North Arcot, (Tamil Nadu State).	Representing the interests of fermers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Mir Shoukath Ali, Master Craftsman, Mysore.	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri S. R. Thakur, Panaji, Goa.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. 9-4/49/73-BO. I-6]

निर्देश: सं०/फा० 9-4(32)/72-बी०ओ० 1-(जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का० आ० 559.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए मैण्ट्रल बैंक आफ इंण्डिया के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1 डा० जे० जे० निस्सरकर, इन्दौर ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
2. श्री रामसिया कुंवर, रीवा (मध्य प्रदेश राज्य)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
3. श्री टी० एम० पपोला, औद्योगिक अर्थ शास्त्र में रीडर, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—
4. श्री रोमेश थापर, पत्रकार, नई दिल्ली ।	
5. श्री आर० रत्नम, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—

[सं० 9-4/49/73-बी०ओ०-1-1]

Ref : No. F.9-4 (32)/72 BOI (Vol) III 4 dated the 4th Dec. 1974

S. O. 559—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Central Bank of India, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975:—

1. Dr. J. J. Nerurkar, Indore.	Representing the interests of depositors of the said Bank—in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
2. Shri Ramsiya Kunder, Rewa (Madhya Pradesh State).	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
3. Shri T. S. Papola, Reader in Industrial Economics, University of Bombay, Bombay.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.
4. Shri Romesh Thapar, Journalist, New Delhi.	
5. Shri R. Ratnam, Tiruchirapalli (Tamil Nadu).	

[No. 9-4/49/73-BO. I-11]

निर्देश : सं० फा० 9-4(32)/72-बी०ओ० 1(जिल्द 3)-4 तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का०आ० 560.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित व्यक्तियों को, 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री ए० आर० सुले, अधिकारी, मुख्य कार्यालय, बैंक आफ इंडिया, मुम्बई।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं।
2. श्री जी०डी० पारीख, मुम्बई।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) के अनुसरण में उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
3. ब्रिगेडियर के० के० वर्मा, रायपुर (मध्य प्रदेश)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
4. श्री रहमतउल्लाह अंसारी, वाराणसी	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
5. श्री मनोहर सिंह मेहता, इंदौर 6. श्री सुकरु भगत, ओराव टोली, जिला राँची (बिहार राज्य) 7. श्री बी०एल० पासी, नई दिल्ली 8. श्री शंकरराव आर० खरत, पूना	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुरक्षण में—

[स०फा० 9-4/49/72-बी०ओ० 1-2]

Ref No.F.9-4(32)/72-BOI-(Vol. III)-4 dated the 4th Dec., 1972.

S.O. 560—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints the following persons to be the Directors of Bank of India, for the period commencing on 7th February 1974 and ending with 10th December, 1975 :—

1. Shri A.R. Sule, Officer, Head Office, Bank of India, Bombay.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri G.D. Parikh, Bombay.	Representing the interest of depositors of the said Bank in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Brig. K.K. Verma, Raipur, (Madhya Pradesh)	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Rahmatullah Ansari, Varanasi.	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri Manohar Singh Mehta, Indore. 6. Shri Sukru Bhagat, Oraon Toli, District Ranchi, (Bihar State). 7. Shri B.L. Passi, New Delhi. 8. Shri Shankarrao R. Kharat, Poona.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. F. 9-4/49/73-BOI-2]

निर्देश : सं०फा० 9-4(32)/72-बी०ओ० 1(जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का० आ० 561.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित व्यक्तियों को 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के निदेशकों के रूप मे नियुक्त करती है :—

1. श्री आई० एस० अहलुवालिया, ज्येष्ठ कार्मिक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली।	खण्ड 3 के उपखंड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं।
2. डा० ए० एस० कहलों, डीन, कालेज आफ बेसिक साइंसेज एण्ड ह्यूमनीटीज, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
4. श्री सत्येन्द्र नाथ भार्गव, 'कोठी', गदाबाद, जिला मथुरा (उ० प्र०)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
4. श्री मदन मोहन महाजन, पानीपत (हरियाणा राज्य)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
5. श्री मोहम्मद अब्दुल्ला, एशिया क्राफ्टस, श्रीनगर। 6. श्री बी० एन० काक, प्रबन्ध निदेशक, राज्य होटल निगम 'वसुन्धरा', जयपुर। 7. श्री बी० एम० गोगटे, अध्यक्ष, गोगटे ग्रीहन महाराष्ट्र स्टील लि०, पूना। 4 8. श्री विमल नारायण महरोत्रा, प्रबंध भागीदार, मेसर्स सीड फार्म, कानपुर (उ०प्र०)	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—

[स०फा० 9-4/49/73 बी०-ओ०-1-3]

Ref : No. F. 9-4(32)/72-BOI-(Vol. III)-4 dated the 4th December, 1972.

S. O. 561.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central, Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Punjab National Bank, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975 :—

1. Shri I.S. Ahluwalia, Senior Personnel Officer, Head Office, Punjab National Bank, New Delhi.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Dr. A.S. Kahlon, Dean, College of Basic Sciences and Humanities, Punjab Agricultural University, Ludhiana.	Representing the interests of depositors of the said Bank, in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri Satyendra Nath Bhargava, 'Kothi', Sadabad Distt. Mathura (U.P.)	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Madan Mohan Mahajan, Panipat (Haryana State).	Representing the interest of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri Mohamad Abdullah, Asia Crafts, Srinagar. 6. Shri V.N. Kak, Managing Director, State Hotels, Corporation, 'Vasundhara', Jaipur. 7. Shri B.M. Gogte, Chairman, Gogte Brihan Maharashtra Steels Ltd., Poona. 8. Shri Bimal Narain Mehrotra, Managing Partner, M/s Seed Farm, Kanpur (U.P.)	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. F. 9-4/49/73-BOI-3]

निर्देश : स०फा० 9-4(32)/72-बी०ओ० 1(जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का० आ० 562.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को 7 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बैंक आफ बड़ोदा के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री के० सी० चोकशी, प्रबन्धक (प्रभार), मुम्बई मुख्य कार्यालय, बैंक आफ बड़ोदा, मुम्बई ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं ।
2. श्री डी० के० देसाई, कृषि और सहकारिता में प्रबंधतंत्र का प्राचार्य, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में—उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
3. सरदार अर्जन सिंह अहूजा, श्री गंगानगर (राजस्थान राज्य)	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
4. श्री जयगोपाल विग, अमृतसर	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना ।
5. श्री विजय एस० महाजनी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स ओजास इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०, पूना । 6. श्री आर० के० राय, पत्रकार, मुम्बई । 7. डा० टी० आर० एस० गोयल, प्रबंध निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स इण्डिया लि०, गाजियाबाद ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (छ) के अनुसरण में—

[सं० 9-4/49/73-बी०ओ०-1-4]

Ref : No. F. 9-4(32)/72-BOI-(Vol. III)-4 dated the 4th December, 1972.

S.O. 562.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions.) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons to be the Directors of Bank of Baroda, for the period commencing on 7th February, 1974 and ending with 10th December, 1975 :—

1. Shri K.C. Chokshi, Manager (Credit), Bombay Main Office, Bank of Baroda, Bombay.	Representing the employees of the said Bank who are not workmen—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Shri D.K. Desai, Professor of Management in Agriculture and Cooperation, Indian Institute of Management, Ahmedabad.	Representing the interests of depositors of the said Bank-in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Sardar Arjan Singh Ahuja, Sri Ganganagar, (Rajasthan State)	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Jaigopal Vig, Amritsar.	Representing the interest of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Shri Vijay S. Mahajani, Managing Director, M/s Ojas Engineering (Pvt.) Ltd. Poona. 6. Shri R.K. Roy, Journalist, Bombay. 7. Dr. T.R.S. Goel, Managing Director, Electronics & Computers India Ltd., Ghaziabad.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. F. 9-4/49/73-BOI-4]

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1974

निर्देश : सं० फा० 9-4/32/72-बी० ओ० 1(जिल्द 3)-4, तारीख 4 दिसम्बर, 1972

का० आ० 563.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों, को 11 फरवरी, 1974 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री एस० डी० पारेलकर, अधिकारी, मुख्य कार्यालय, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता ।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में—उक्त बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना, जो कर्मकार नहीं हैं ।

2. डा० डी० बनर्जी, निदेशक, नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता।	खण्ड 3 के उपखंण्ड (ग) के अनुसरण में —उक्त बैंक के निक्षेपकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
3. श्री पन्नालाल दास गुप्ता, कलकत्ता।	खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में —कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
4. श्री गुरशरण सिंह, बुंडाला। जिला—जलंधर।	खण्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में—कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
5. डा० उपेन बोडोलोई, आर्थिक विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी।	खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के के अनुसरण में—
6. श्री जी० पी० सिन्हा, श्रम और सामाजिक कल्याण विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 7. श्री गोपीनाथ महन्ती, भूवनेश्वर।	खंड 3 के उपखंड (च) के अनुसरण में—

[सं० 9-4/49/73-बी०ओ० I-5]

द० म० सुकथनकर, निदेशक

New Delhi, the 11th February, 1974

Ref : No. F. 9-4(32)/72 -BOI-(Vol. III)-4 dated the 4th December, 1972.

S.O. 563.—In pursuance of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints the following persons to be the Directors of United Commercial Bank, for the period commencing on 11th February, 1974 and endng with 10th December 1975:—

1. Shri S.D. Parelkar, Officer Head Office, United Commercial Bank, Calcutta.	Representing the employees of the said Bank who are not work men—in pursuance of sub-clause (c) of clause 3.
2. Dr. D. Banerjee, Director, National Rubber Manufacturers Ltd., Calcutta.	Representing the interests of depositors of the said Bank in pursuance of sub-clause (d) of clause 3.
3. Shri Pannalal Das Gupta, Calcutta.	Representing the interests of farmers—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
4. Shri Gursaran Singh, Bundala, Distt. Jullundur.	Representing the interests of artisans—in pursuance of sub-clause (e) of clause 3.
5. Dr. Upen Bordoloi, Department of Economics, Gauhati University, Gauhati.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.
6. Shri G.P. Sinha, Department of Labour and Social Welfare University of Patna, Patna. 7. Shri Gopinath Mohanty, Bhubaneswar.	—in pursuance of sub-clause (f) of clause 3.

[No. F 9-4/49/73-BOI-5]

D.M. SUKTHANKAR, Director.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

का० आ० 564.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी 1974 की 11 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	31,45,19,000		सोने का सिक्का और बुलियन.		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
संचलन में नोट . .	5777,70,08,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	. .	
			विदेशी प्रतिभूतियां .	101,73,97,000	
जारी किए गये कुल नोट		5809,15,27,000	जोड़		284,27,02,000
			रुपये का सिक्का .		9,54,58,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . .		5515,33,67,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र . .		. .
कुल देयताएं		5809,15,27,000	कुल आस्तियां .		5809,15,27,000

11 जनवरी 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्य-कलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	31,45,19,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,99,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,12,000
		खरीदे और भुनाये गए बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000	(क) देशी	130,66,55,000
		(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	205,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	252,51,30,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया *	216,63,00,000
जमा राशियां :—		निवेश**	475,72,94,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	64,33,66,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	11,27,69,000	(ii) राज्य सरकारों को×	107,10,08,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	695,31,50,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	234,45,85,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,69,20,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	279,89,72,000
		(iii) दूसरों को	3,25,30,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,28,11,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	51,25,000	(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	66,85,33,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,80,15,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	34,00,00,000
(ग) अन्य	72,38,12,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,10,36,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	112,78,87,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	58,90,91,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
अन्य देयताएं	479,35,00,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	139,20,04,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	73,30,87,000
रुपये	2135,93,70,000	रुपये	2135,93,70,000

*नकदी, आवधिक, जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है।

×राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं; परन्तु राज्य सरकारों को दिये गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 25,00,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

तारीख, 16 जनवरी, 1974

[स० फ० 10(1)/74—बी०ओ०I]

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 16th February, 1974

S. O. 564—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 11th day of January 1974

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	31,45,19,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5777,70,08,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
Total Notes issued		5809,15,27,000	(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	101,73,97,000	
			Total		284,27,02,000
			Rupee Coin		9,54,58,000
			Government of India Rupee Securities		5515,33,67,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial papers		..
Total Liabilities		5809,15,27,000	Total Assets		5809,15,27,000

R.K. HAZARI, Dy. Governor

Dated the 16th January, 1974

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 11th day of January, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	31,45,19,000
		Rupee Coin	2,99,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,12,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	(a) Internal	130,66,55,000
		(b) External	..
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	(c) Government Treasury Bills	252,51,30,000
		Balances Held Abroad*	216,63,00,000
		Investments**	475,72,94,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	107,10,08,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	234,45,85,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks‡	279,89,72,000
(i) Central Government	64,33,66,000	(iii) Others	3,25,30,000
(ii) State Governments	11,27,69,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	695, 31,50,000	(i) State Governments	66,85,33,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,69,20,000	(ii) State Co-operative Banks	20,80,15,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,28,41,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	51,25,00 0	(iv) Agricultural Refinance Corporation	34,00,00,000
(c) Others	72,38,12,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	11,10,36,000
Bills Payable	112,78,87,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	58,90,91,000
Other Liabilities	479,35,00,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	139,20,04,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	73,30,87,000
Rupees	2135,93,70,000	Rupees	2135,93,70,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short term Securities.

**Excluding investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultual Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 25,00,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 16th day of January, 1974

R. K. HAZARI Dy. Governor

[No. F 10(1)/74 B. O.I]

का० आ० 565-रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी 1974 की 18 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	27,58,32,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	.	
संचलन में नोट . .	5812,17,78,000		विदेशी प्रतिभूतियां .	101,73,97,000	
			जोड़ .		284,27,02,000
जारी किये गये कुल नोट .		5839,76,10,000	रुपये का सिक्का . .		10,15,61,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . .		5545,33,47,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र . .		..
कुल देयताएं		5839,76,10,000	कुल आस्तियां		5839,76,10,000

तारीख. 23 जनवरी 1974

एस० जगन्नाथन गवर्नर

18 जनवरी 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	27,58,32,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,56,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि .	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,35,000
		खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि . .	85,00,00,000	(क) देशी	142,41,62,000
		(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	205,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल . . .	262,63,81,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया* . . .	216,74,67,000
जमा राशियां :—		निवेश** . .	430,81,80,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार . . .	52,01,21,000	(i) केन्द्रीय सरकार को . . .	..
(ii) राज्य सरकारें . . .	11,92,59,000	(ii) राज्य सरकारों को@ . . .	134,14,13,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	778,20,81,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† . .	291,33,15,000
(i) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	13,10,98,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡ . .	279,27,58,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	1,17,41,000	(iii) दूसरों को	3,93,80,000
(iv) अन्य बैंक . . .	84,83,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम	
		(i) राज्य सरकारों को . .	66,83,83,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	20,46,18,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को . .	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को . .	34,00,00,000
(ग) अन्य	71,79,54,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,10,36,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	102,81,37,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . .	58,43,54,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से	
अन्य देयताएं	479,12,41,000	ऋण अग्रिम और निवेश	..
		(क) विकास बैंकों को ऋण और अग्रिम . .	141,51,05,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां . . .	73,71,40,000
रुपये .	2195,01,15,000	रुपये .	2195,01,15,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 32,00,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

तारीख : 23 जनवरी 1974

एस० जगन्नाथन गवर्नर

[सं० फा० 10(1)74-बी. ओ. I]

S.O. 565.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 18th day of January 1974

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	27,58,32,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5812,17,78,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
			(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	101,73,97,000	
Total Notes issued		5839,76,10,000			
			Total		284,27,02,000
			Rupee Coin		10,15,61,000
			Government of India Rupee Securities		5545,33,47,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		5839,76,10,000	Total Assets		5839,76,10,000

Dated the 23rd January, 1974

S. JAGANNATHAN, Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 18th January 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	27,58,32,000
		Rupee Coin	2,56,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,35,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	(a) Internal	142,41,62,000
		(b) External	..
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	(c) Government Treasury Bills	262,63,81,000
		Balances Held Abroad*	216,74,67,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	Investments**	430,81,80,000
		Loans and advances to :—	
		(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	134,14,13,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	291,33,15,000
(i) Central Government	52,01,21,000	(ii) State Co-operative Banks‡	279,27,58,000
(ii) State Governments	11,92,59,000	(iii) Others	3,93,80,000
(b) Banks		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(i) Scheduled Commercial Banks	778,20,81,000	(a) Loans and Advances to :—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	13,10,98,000	(i) State Governments	66,83,83,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,17,41,000	(ii) State Co-operative Banks	20,46,18,000
(iv) Other Banks	84,83,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(c) Others	71,79,54,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	34,00,00,000
Bills Payable	102,81,37,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,10,36,000
Other Liabilities	479,12,41,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	..
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	58,43,54,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	141,51,05,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	73,71,40,000
Rupees	2195,01,15,000	Rupees	2195,01,15,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments form the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 32,00,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 23rd day of January, 1974

S. JAGANNATHAN, Governor

[No. F. 10 (1)/74—B.O.I.]

का० आ० 566.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में फरवरी 1974 की 8 तारीख को समाप्त हुये सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयतायें	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	37,87,00,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	5920,39,47,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—	
जारी किये गये कुल नोट		5958,26,17,000	विदेशी प्रतिभूतियां	101,73,97,000	
			जोड़		284,27,02,000
			रुपये का सिक्का		8,66,86,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5665,32,59,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयतायें		5958,26,47,000	कुल आस्तियां		5958,26,47,000

तारीख : 13 फरवरी, 1974

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

3 फरवरी, 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयतायें	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	37,87,00,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,07,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,03,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	205,00,00,000	(क) देशी	171,44,58,000
जमा राशियां :—		(ख) विदेशी	..
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	298,46,46,000
(i) केन्द्रीय सरकार	55,80,71,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	254,43,90,000
(ii) राज्य सरकारें	11,23,68,000	निवेश**	315,90,71,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	669,92,53,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15,57,16,000	(ii) राज्य सरकारों को†	110,89,47,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,21,45,000	ऋण और अग्रिम :—	
(iv) अन्य बैंक	57,92,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को×	255,80,75,000
(ग) अन्य	70,78,47,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को××	284,18,33,000
देय बिल	147,35,85,000	(iii) दूसरों को	4,37,55,000
अन्य देयतायें	497,89,62,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को	66,71,48,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,05,62,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	39,00,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,10,36,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	56,16,31,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	151,10,59,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	76,78,18,000
रुपये	2154,37,39,000	रुपये	2154,37,39,000

*नकदी, अवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है।

×रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 32,00,00,000/- रुपये शामिल है।

××राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

तारीख : 13 फरवरी, 1974

[सं०फ० 10 (1)/74-बी०ओ०-I]

S. O. 566—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 8th day of February, 1974

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	37,87,00,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5920,39,47,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
Total Notes issued		5958,26,47,000	(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	101,73,97,000	
			Total		284,27,02,000
			Rupee Coin		8,66,86,000
			Government of India Rupee Securities		5665,32,59,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		5958,26,47,000	Total Assets		5958,26,47,000

Dated the 13th day of February, 1974. L. R. KATARIA, Sec. Officer R.K. HAZARI, Dy. Governor.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 8th February, 1974

New Delhi, the 16th February, 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	37,87,00,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	3,07,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	Small Coin	3,03,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	(a) Internal	171,44,58,000
Deposits :—		(b) External	..
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	298,46,46,000
(i) Central Government	55,80,71,000	Balances Held Abroad*	254,43,90,000
(ii) State Governments	11,23,68,000	Investments**	315,90,71,000
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	669,92,53,000	(i) Central Government	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,57,16,000	(ii) State Governments@	110,89,47,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,21,45,000	Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	57,92,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	255,80,75,000
(c) Others	70,78,47,000	(ii) State Co-operative Banks‡	284,18,33,000
Bills Payable	147,35,85,000	(iii) Others	4,37,55,000
Other Liabilities	497,89,62,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	66,71,48,000
		(ii) State Co-operative Banks	20,05,62,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	39,00,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,10,36,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	56,16,31,000
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	151,10,59,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	76,78,18,000
RUPEES	2154,37,39,000	Other Assets	
		RUPEES	2154,37,39,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 32,00,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 13th day of February, 1974.

[No. F. 10(1)/74 BOI]

R. K. HAZARI, Dy. Governor.

का० आ० 567.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी, 1974 की 25 तारीख को समाप्त हुये सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयतायें	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	23,38,78,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—	
संचलन में नोट	5797,87,94,000		विदेशी प्रतिभूतियां	101,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		5821,26,72,000	जोड़		284,27,02,000
			रुपये का सिक्का		11,66,68,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5525,33,02,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयतायें		5821,26,72,000	कुल आस्तियां		5821,26,72,000

तारीख : 30 जनवरी, 1974

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

25 जनवरी, 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	23,38,78,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,30,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,34,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थितिकरण) निधि	85,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाये) निधि	205,00,00,000	(क) देशी	149,43,15,000
जमा राशियां :—		(ख) विदेशी	..
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	287,62,18,000
(i) केन्द्रीय सरकार	52,76,21,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	237,25,85,000
(ii) राज्य सरकारें	13,69,13,000	निवेश**	411,98,13,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	753,99,14,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15,35,79,000	(ii) राज्य सरकारों को@	144,41,79,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,28,76,000	ऋण और अग्रिम :—	
(iv) अन्य बैंक	50,81,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	229,40,20,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	280,40,62,000
		(iii) दूसरों को	3,84,55,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	66,82,98,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,40,16,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	39,00,00,000
(ग) अन्य	75,55,65,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,10,36,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण	
देय बिल	100,69,38,000	और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	56,86,79,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
अन्य देयतायें	482,43,97,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	143,13,10,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	75,14,56,000
रुपये	2180,28,84,000	रुपये	2180,28,84,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 32,00,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 30 जनवरी, 1974

[सं०फ० 10(1)/74-बो० औ० I]

गवर्नर

ISSUE DEPARTMENT

S. O. 567.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 25th day of January, 1974

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	23,38,78,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5797,87,94,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
			(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	101,73,97,000	
Total Notes issued		5821,26,72,000			
			TOTAL		284,27,02,000
			Rupee Coin		11,66,68,000
			Government of India Rupee Securities		5525,33,02,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		5821,26,72,000	Total Assets		5821,26,72,000

Dated the 30th day of January, 1974

S. JAGANNATHAN, Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 25th January 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	23,38,78,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,30,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	Small Coin	3,34,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	(a) Internal	149,43,15,000
Deposits :—		(b) External	..
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	287,62,18,000
(i) Central Government	52,76,21,000	Balances Held Abroad*	237,25,85,000
(ii) State Governments	13,69,13,000	Investments**	411,98,13,000
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	753,99,14,000	(i) Central Government	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,35,79,000	(ii) State Governments@	144,41,79,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,28,76,000	Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	50,81,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	229,40,20,000
(c) Others	75,55,65,000	(ii) State Co-operative Banks‡	280,40,62,000
Bills Payable	100,69,38,000	(iii) Others	3,84,55,000
Other Liabilities	482,43,97,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :	
		(i) State Governments	66,82,98,000
		(ii) State Co-operative Banks	20,40,16,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	39,00,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,10,36,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	56,86,79,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	142,13,10,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	75,14,56,000
Rupees	2180,28,84,000	Rupees	2180,28,84,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 32,00,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

No. F. 10(1)/74 B.O. I

Dated the 30th day of January, 1974.

S. JAGANNATHAN, Governor.

वित्त विभाग

का० आ० 568.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में फरवरी 1974 की 1 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	20,82,06,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
संचलन में नोट . .	5819,14,30,000		विदेशी प्रतिभूतियां .	101,73,97,000	
			जोड़ .		284,27,02,000
जारी किये गये कुल नोट .		5839,96,36,000	रुपये का सिक्का . .		10,37,14,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . .		5545,32,20,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र . .		..
कुल देयताएं .		5839,96,36,000	कुल आस्तियां . .		5839,96,36,000

तारीख : 6 फरवरी, 1974

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

1 फरवरी 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	20,82,06,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,58,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,31,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि .	85,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
		(क) देशी	159,29,64,000
		(ख) विदेशी	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल . .	257,34,57,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	205,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* . . .	245,40,90,000
जमाराशियां:—		निवेश** . . .	453,84,92,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार . .	50,89,41,000	(i) केन्द्रीय सरकार को . . .	..
(ii) राज्य सरकारें . . .	19,10,69,000	(ii) राज्य सरकारों को‡ . .	107,56,20,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक .	755,38,28,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को@ .	292,36,60,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	14,92,15,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को†† .	284,16,55,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,29,56,000	(iii) दूसरों को . .	5,47,55,0002
(iv) अन्य बैंक . . .	85,05,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को . .	66,80,92,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	20,36,39,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को . .	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को .	39,00,00,000
(ग) अन्य	73,59,01,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,10,36,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	56,68,79,000
देय बिल	150,25,87,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . .	118,24,10,000
अन्य देयताएं	496,04,57,000	(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश . . .	..
		अन्य आस्तियां	77,76,15,000
रुपये .	2246,34,59,000	रुपये .	2246,34,59,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है ।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है ।

@रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 32,00,00,000/ रुपये शामिल है ।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

तारीख : 6 फरवरी, 1974.

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

एल० आर० कटारिया, अनुभाग अधिकारी

[सं० फा० 10(1)/74-बी०ओ० 1]

ISSUE DEPARTMENT

S.O. 568.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 1st day of February, 1974.

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	20,82,06,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5819,14,30,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
			(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	101,73,97,000	
Total Notes issued		5839,96,36,000			
			Total		284,27,02,000
			Rupee Coin		10,37,14,000
			Government of India Rupee Securities		5545,32,20,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		5839,96,36,000	Total Assets		5839,96,36,000

Dated the 6th day of February, 1974 R. K. HAZARI, Dy. Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 1st February, 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	20,82,06,000
Reserved Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	5,58,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	Small Coin	3,31,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	(a) Internal	159,29,64,000
Deposits :—		(b) External	..
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	257,34,57,000
(i) Central Government	50,89,41,000	Balances Held Abroad*	245,40,90,000
(ii) State Governments	19,10,69,000	Investments**	453,84,92,000
(b) Banks		Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	755,38,28,000	(i) Central Government	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,92,15,000	(ii) State Governments@	107,56,20,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,29,56,000	Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	85,05,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	292,36,60,000
(c) Others	73,59,01,000	(ii) State Co-operative Banks‡	284,16,55,000
Bills Payable	150,25,87,000	(iii) Others	5,47,55,000
Other Liabilities	496,04,57,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.	
		(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	66,80,92,000
		(ii) State Co-operative Banks	20,36,39,000
		(iii) Central Land Mortgage Bank	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	39,00,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,10,36,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	56,68,79,000
		Loans, Advances and Investment from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	148,24,10,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	77,76,15,00J
Rupees	2246,34,59,000	Rupees	2246,34,59,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 32,00,00,000/- advance to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stablilisation) Fund.

R. K. HAZARI, Dy. Governo

Dated the 6th day of February, 1974. L. R. KATARIA, Section officer. No. F. 10(1)/74 BO.

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क समाहरणालय, पश्चिम बंग

सीमा-शुल्क

कलकत्ता, 12 दिसम्बर, 1973

का०आ० 569.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा 34 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, पश्चिम बंग जो पश्चिम बंग केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा-शुल्क समाहरणालय के क्षेत्राधिकार में समाहर्ता सीमा-शुल्क नियुक्त हुए हैं, एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट दर्जे के अधिकारियों एवं उनसे ऊपर के दर्जे के अधिकारियों को, जे० के० स्टील इन्डस्ट्रीज लि०, रिसड़ा, जिला—हुगली के "बंधित भाण्डागार" के कार्य के ऊपर अधीक्षण के उद्देश्य से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं में निर्दिष्ट "समुचित अधिकारी" जैसा कि कथित अनुसूची के समग्र स्तंभ (2) में दिखाये गये हैं, नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

(1)	(2)
केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क अधीक्षक एवं हिंद मोटर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रेंज, पो० उत्तरपाड़ा, जिला—हुगली के केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क निरीक्षक	60, 62, 64, 67, 68, 69 तथा 72

[अधि. सं. 1/73—सी० एस० ओ० (40) 1-कस/डब्लूबी/71/26638C]

एन० एन० रायचौधरी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS : WEST BENGAL

CUSTOMS

Calcutta, 12th December, 1973

S.O. 569.—In exercise of the powers conferred by sub-section 34 of Section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Collector of Central Excise, West Bengal, Calcutta, having been appointed as the Collector of Customs within the jurisdiction of West Bengal Central Excise and Customs Collectorate, hereby assigns to the officers of and above the rank of the officers mentioned in the column (1) of the schedule below, the functions of the "Proper Officer" referred to in the various sections of the Customs Act, 1962 given in the corresponding entry in Column (2) of the said Schedule, for the purpose of supervision over the working of the "Bonded Warehouse" of M/s. J. K. Steel & Industries Ltd. at Rishra in the district of Hooghly.

SCHEDULE

(1)	(2)
Superintendent of Customs & Central Excise & Inspector of Customs & Central Excise of Hind Motor Central Excise Range, P.O. Uttarpara, District—Hooghly.	60, 62, 64, 67, 68, 69 and 72.

[Notification No. 1/73—C. No. VIII(40) 1-CUS/WB/71/26638C]

N. N. ROY CHOUDHURY, Collector

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1974

का०आ० 570.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं फीस) अधिनियम 1948 (1948 का 41) के खंड 2 की धारा (क) का अनुसरण करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, मदान स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास में सहायक, श्री जगत सिंह को, तत्काल से, कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फाईल सं० टी० 4330/3/72]

राम लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th February, 1974

S.O. 570.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri Jagat Singh, Assistant in the Consulate General of India, Medan, to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330/3/72]

RAM LAL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1973

का०आ० 571.—सर्वश्री रेडले स्पोर्टस, डब्ल्यूएक्स, 66 बस्ती नौ रोड, जलन्धर-2को 52087 रु० का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/2660361/सी/एक्स/एक्स/46/डी/35-36, दिनांक 31-3-73 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति मात्र) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस का 12727 रु० तक के लिए उपयोग कर लिया गया था और अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता शेष मूल्य अर्थात् 39360 रु० को पूरा करने के लिये है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या : पी/एल/2660361/सी, दिनांक 31-3-73 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई थी और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[सं० एसजी, 14/ओ डी,/72/एससी- 4/सीएलए/1851 से 1887]

ओ० एन० आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)

(Central Licensing Area)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 12th October, 1973

S.O. 571.—M/s. Redlay Sports, WX. 66 Basti Nau Road, Jullundur-2 were granted import licence No. P/L/2660361/C/XX/46/D/35-36 dated 31-3-73 for Rs. 52087. They have applied for duplicate copy (Custom purposes copy only) of

the above licence on the ground that original copy of the said licence have been lost/misplaced. It is further stated that the original licence was utilised up to Rs. 12727 and that the duplicate copy is required to cover the balance amount of Rs. 39360.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original custom purposes copy of the licence No. P/L/2660361/C dated 31-3-73 has been lost and direct that the duplicate copy of the licence should be issued to the applicant. The original Custom purposes copy of the licence is cancelled.

[File No. SG. 14/OD.72/SC. IV/CLA/1851 to 1887]

A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

कलकत्ता, 12 सितम्बर 1973

का.आ. 572.—सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स, 3, बरेटो लेन, कलकत्ता-1 को संबद्ध लाइसेन्स अवधि की रैडबुक (वा-1) के परिशिष्ट 26 में सम्मिलित मोटर व्हीकल पुर्जों (अन्य मदों में से) के आयात के लिए इस कार्यालय द्वारा लाइसेन्स सं० (1) पी/एस/1703174/सी दिनांक 20-10-71 मूल्य 37,281 रुपये, (2) पी/एस/1702779/सी दिनांक 16-9-71 मूल्य 15,888 रुपये, (3) पी/एस/1704801/सी दिनांक 27-3-72 मूल्य 27,718 रुपये, (4) पी/एस/1704802/सी दिनांक 27-3-72 मूल्य 13,859 रुपये, (5) पी/एस/1704803/सी दिनांक 27-3-72 मूल्य 13,859 रुपये जारी किए गए थे ।

उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित लाइसेन्स उद्योग निदेशक, पं० बंगाल द्वारा जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र सं० आर-एस-एस आई/इम्प/116/70-71/45 दिनांक 20-5-71 और आर-एस-एस-आई/ई/1/116/71-72/206 दिनांक 4-2-72 के आधार पर जारी किए गए थे । परन्तु लाइसेन्स अवधि अप्रैल-मार्च 71 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक, वा-1 में निहित आयात नीति के अनुसार आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की क्रम सं० 293,95 एंड 97/4 के अंतर्गत वर्गीकृत मोटर व्हीकल पुर्जों का आयात राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन सहयोग समितियों और 25 पोत या इससे अधिक पोतसमूह के स्वामियों के अतिरिक्त अन्य वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए अनुमित नहीं था । (देखिए सबद्ध रैडबुक का परिशिष्ट 26) । आटोमोबाइल संघटकों के विनिर्माण के लिए संघटकों के रूप में भी उन पुर्जों के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को कोई लाइसेन्स प्रदान करना तब तक अनुमेय नहीं था जब तक ऐसे संघटकों के आयात की प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार विशेष रूप से सिफारिश न कर दी जाए और देशीय दृष्टिकोण से अनुज्ञा न दे दी जाए (देखिए लाइसेन्स अवधि अप्रैल-मार्च 71 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक, वा-1 के परिशिष्ट 40 के नीचे टिप्पणी) । तत्पश्चात् जिन प्रायोजक/प्राधिकारियों ने पूर्वोक्त अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किया था उनको भी इस बात का सत्यापन करने के लिए हवाला भेजा गया था कि क्या उनके द्वारा ऊपर उल्लिखित अनुदेश के अनुसार मदों की सिफारिश की गई थी । परन्तु उन्होंने यह सूचना दी थी कि सिफारिश करने से पहले उन्होंने कोई देशी अनुज्ञा अपनी ओर से प्राप्त नहीं की थी ।

इस के पश्चात् सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स कलकत्ता को एक कारण निर्देशन नोटिस सं० 16-1/पी/डी आई/आई डी ए/12/71-72/ए यू०4/3312 दिनांक 16-3-73 यह पूछते हुए जारी किया गया था कि इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए गए उक्त लाइसेन्स धारा 9, उपधारा (ए) तथा (बी) के अनुसार इस आधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिए कि वे भूल से और नियमों अथवा आयात (नियंत्रण) आदेश, '55' की शर्तों के प्रतिकूल जारी किए गए थे ।

पूर्वोक्त कारण निर्देशन नोटिस के उत्तर में सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स, कलकत्ता ने अपने पत्र दिनांक 30-3-73 द्वारा उन पर लगाए गए आरोप की व्याख्या के लिए और जिस भूल से उनको लाइसेन्स जारी किए गए थे उसके स्वरूप के लिए पूछा ।

श्री आर० के० तिवारी, एडवोकेट ने इस कार्यालय में प्राप्त एक पत्र दिनांक 26-5-73 का उत्तर सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स, कलकत्ता को विधिवत दिया गया था देखिये इस कार्यालय का सम संख्या पत्र दिनांक 21-8-73 जिसमें मामले का विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया गया था । उसी पत्र में सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स, कलकत्ता को दिनांक 1-9-73 को 3 बजे अपराह्न का समय व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रदान किया गया था । उसी पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि यदि सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स, कलकत्ता अपने प्रतिवेदन की पुष्टि में मूलरूप में सभी प्रमाण्य दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होने में असमर्थ रहे अथवा यह कि वे व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मामले की व्याख्या करने में असमर्थ रहे तो उन को आगे कोई हवाला दिए बिना मामले का निर्णय इस कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा ।

सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स को उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस के विरोध में प्रतिवेदन करने के लिए पर्याप्त समय और सुअवसर मिलने पर भी वे निश्चित तिथि और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहे और उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया देखिये उनका पत्र सं० आई सी टी/इम्प/116/70-71/45/73 दिनांक 29-8-73 और उनका आवेदन उपर्युक्त कारण से स्वीकृत न किया जा सका ।

अधोहस्ताक्षरी ने इस कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और इस निर्णय पर पहुंचा है कि ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लाइसेन्स भूल से और नियमों अर्थात् संबद्ध लाइसेन्स अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक वा-1 में प्रकाशित आयात नीति के प्रतिकूल जारी किए गए थे । पिछले पैराग्राफों में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेन्स रद्द कर देने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर देने चाहिए ।

इसलिए अधोहस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9, उप-धारा (ए) तथा (बी) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री इन्डोजर्मन ट्रेडर्स, 3, बरेटो लेन, कलकत्ता-1 को जारी किए गए लाइसेन्स संख्या (1) पी/एस/1703174/सी, (2) पी/एस/1702779/सी, (3) पी/एस/1704801/सी, (4) पी/एस/1704802/सी, (5) पी/एस/1704803/सी को एतद्द्वारा रद्द करता है ।

[सं० 132/73/ई एण्ड एल]

टी० टी० लो, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Calcutta, the 12th September, 1973

S.O. 572.—Licence Nos.(1) P/S/1703174/C dated 20-10-71 for Rs. 37,281, (2) P/S/1702779/C dated 16-9-71 for Rs. 15,888, (3) P/S/1704801/C dated 27-3-72 for Rs. 27,718 (4) P/S/1704802/C dated 27-3-72 for Rs 13,859, (5) P/S/1704803/C dated 27-3-72 for Rs. 13,859 were issued by this office to M/s. Indo German Traders, 3, Baretto Lane Calcutta-1 for import of M. V. Parts (amongsts other items covered by Appendix-26 to the Red Book (Vol. 1) of the relevant licensing period.

Licences mentioned in para 1 above were issued on the basis of Essentiality Certificate No. R-SSI/Imp/116/70-71/4 dated 20-5-71 and R-SSI/E/1/116/71-72/206 dated 4-2-72 issued by Director of Industries, West Bengal. But according

to import policy contained in Import Trade Control Policy Book, Vol. I for the licensing period April—March 1971 import of M. V. Parts, classified under serial 293, 95 and 97/IV of the Import Trade Control schedule were not permissible to actual users other than the State Transport Authority, Co-operative Societies of Transport and fleet owners owning fleet of 25 vehicles or above (vide Appendix 26 to the relevant Red Book). No licence to Actual Users was also permissible for those M. V. Parts as components for the manufacture of automobile components unless import of such components was specifically recommended by the sponsoring authorities according to the approved manufacturing programme and cleared from indigenous angle (vide note below Appendix 40 to the Import Trade Control Policy Book, Vol. I for the licensing period April—March 1971). Reference was also made, subsequently, to the sponsoring authorities who issued the aforesaid essentiality certificate, for verification whether the items were recommended by him in terms of instruction referred to above. But it was reported by him that no indigenous clearance was obtained by him before recommendation from his end.

Thereafter, a show cause notice No. 16-1/P/DI/IDA/12/71-72/AU. IV/3312 dated 16-3-73 was issued to M/s. Indo German Traders. Calcutta to show cause within 15 days from the date of issue of the notice as to why the said licences issued in their favour should not be cancelled on the ground that the said licences were issued through inadvertance and contrary to the rules or the provisions of Imports (Control) Order 1955 in terms of Clause 9, Sub-clause (a) and (b).

In response to the aforesaid show cause notice M/s. Indo German Traders, Calcutta had by their letters dated 30-3-73 asked for amplification of the charge and the nature of inadvertence through which the licences were issued to them.

A communication dated 26-5-73 from Sri R. K. Tewari, Advocate, received in this office was duly replied to M/s. Indo German Traders, Calcutta vide this office letter of even number dated 21-8-73 wherein the case was explained in detail. In the same letter M/s. Indo German Traders, Calcutta was offered an opportunity of being heard in person at 3 P.M. on 1-9-73. It was also clearly indicated in the same letter that if M/s. Indo German Traders, Calcutta failed to appear for personal hearing with all corroborative documentary evidence, in original, in support of their representation or that they might have to state during the personal hearing, the case will be adjudicated on the basis of documents and evidence available in this office records without further reference to them in the matter.

Inspite of giving M/s. Indo German Traders sufficient time and opportunity for making the representation against the show cause notice mentioned above they failed to turn up for the personal hearing on the appointed date and time and requested for adjournments vide their letter No. ICT/Imp/116/70-71/45/73 dated 29-8-73 and the same could not be acceded to for the reason referred to above.

The undersigned has carefully examined the evidence available in this office and has come to the conclusion that the licences mentioned in para 1 above were issued through inadvertence and contrary to the rules i.e. the import policy published in Import Trade Control Policy Book, Vol. I for the April-March 1971 licensing period. Having regard to what has been stated in the preceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective.

Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under clause 9, sub-clause (a) and (b) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licences Nos. (1) R/S/1703174/C, (2) P/S/1702779/C, (3) P/S/1704801/C, (4) P/S/1704802/C, (5) P/S/1704803/C issued in favour of M/s. Indo German Traders, 3, Baretto Lane, Calcutta-1.

[No. 132/73/E&L]

T. T. LA, Dy. Chief Controller

आदेश

कलकत्ता, 29 अक्टूबर, 1973

विषय :—आयात लाइसेन्स सं० पी/एस/1769614/टी/ओ/आर/44/सी/35-36 दिनांक 18-12-72 मूल्य 2,46,588 रुपये की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति और सीमा-शुल्क निकासी प्रति को रद्द करने और सामान्य लाइसेन्स अनुदेश सं० 10/67 दिनांक 23-3-67 के अनुसार उनकी अनुलिपि प्रतियां जारी करने का आदेश ।

का.आ. 573—सर्वश्री सुप्रिम इन्डस्ट्रीज, डिक्सन रोड, भागलपुर-1, बिहार को 2,46,588 रुपये मूल्य का एक लाइसेन्स सं०पी०/एस/1769614/ओ/आर/44/सी/35-36 दिनांक 18-12-72 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेन्स की सीमा-शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं । यह भी बताया गया है कि मूल लाइसेन्स किसी सीमा-शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं कराया गया है और लाइसेंस के पूरे मूल्य (अर्थात् 2,46,588 रुपये) का उपयोग करना शेष है ।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र इस संबंध में दाखिल किया है कि लाइसेन्स की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एस/1769614/टी/ओ आर/44/सी/35-36 दिनांक 18-12-72 मूल्य 2,16,588 रुपये की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई और निदेश देता हूं कि इन की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जानी चाहिए ।

लाइसेन्स की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है ।

[सं० ए यू/048405/12/ए एम 73/4]

बी० के० बिस्वास, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

Calcutta, the 29th October, 1973

Sub.—Order cancelling Exchange Control and Customs purposes copy of the Import licence No. P/S/1769614/T/OR/44/C/35-36 dated 18-12-72 for Rs. 2,46,588 in connection with the issue of duplicate copy of the same in terms of G.L.I. No. 10/67 dated 23-3-67.

S.O. 573.—M/s. Supreme Industries, Dixon Road, Bhagalpur-1, Bihar were granted licence No. P/S/1769614/T/OR/44/C/35-36 dated 18-12-72 for Rs. 2,46,588. They have applied for duplicate copy of both the Custom purpose and Exchange Control copy of the said licence on the ground that the original of the same had been lost/misplaced. It is further stated that the original licence has not been registered with any Customs authorities and the full value of the licence (i.e. Rs. 2,46,588) remained unutilised.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit to the effect that the original Exchange Control and Custom purposes copy of the licence has been lost/misplaced. I am satisfied that the original Custom purpose and Exchange Control Purposes copy of the licence No. P/S/1769614/T/OR/44/C/35-36 dated 18-12-72 for Rs. 2,46,588 has been lost/misplaced and directed that duplicate copy of the same should be issued to the applicant.

The original Customs purposes and Exchange Control purposes copies of the licence are cancelled.

[No. AU/048405/12/A-M'73/IV]

B. K. BISWAS, Dy. Chief Controller

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1974

का.आ. 574.—सर्वश्री जगदीश आयल इन्डस्ट्रीज (प्रा०)लि० मिल पारा, पारा पोरबन्दर (गुजरात) को वास्तविक उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 21389 रु० का एक लाइसेंस सं० पी०/ए/1341981 दिनांक 9-12-71 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि उसकी मूल प्रति 20998 रु० तक उपयोग करने और नया सीमा शुल्क कार्यालय, बम्बई में पंजीकृत कराने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

उपर्युक्त बयान के समर्थन के आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैंडबुक 1973-74 की कंडिका 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसम्बन्धी, प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं उक्त लाइसेंस के मूल सीमा-शुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैंडबुक, 1973-74 की कंडिका 320(4) की व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा-शुल्क कार्यसम्बन्धी मात्र) प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या वनस्पति/6/ए० एम०-71/ए० यू० एच० एच०/सी एल० ए० 4490]

के० आर० धीर,

उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

(Central Licensing Area)

ORDER

New Delhi, the 9th January, 1974

S.O. 574.—M/s. Shri Jagdish Oil Industries (P) Ltd. Mill Para, Para Porbander (Gujarat) were granted licences No. P/A/1341981 dated 9-12-1971 for Rs. 21389 from G.C.A. under A.U. Category for import of raw material for Vanaspati Mill Machinery.

They have applied for the issue of duplicate Custom purpose copies of the said licences on the ground that the original copy thereof has been lost/misplaced having been utilised upto Rs. 20998 registered with New Custom House, Bombay.

The applicant has filed affidavits in support of the above statement as required under para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1973-74. I am satisfied that the original copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the Powers conferred on me under Section 9 (CC) of Import Control Order, 1955 dt. 7-12-1955, I order the cancellation of the said original Custom Copy of the licence.

The applicant is now being issued duplicate copy (Custom purposes only) of the aforesaid licence in accordance with the provision of para 320(4) of the I.T.C. Hand Book of Rule and Procedure, 1973-74.

[No. Vanaspati/6/AM. 71/AU-HH/CLA/4490]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1974

का.आ. 575.—सर्वश्री जोनसन एंड जोनसन लि०, 30, फोरजट स्ट्रीट, बम्बई को 2,72,000 रुपये (दो लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) के लिये आयात लाइसेंस सं० पी०/सी० 2064058/डी०/आई० ई०/43/एच०/35-36 सि० जी०4 दिनांक 30-6-72 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कुल धन-राशि जिसके लिये मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति का उपयोग किया गया था वह 26,727.54 रुपये है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक, बम्बई के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। इसलिये यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा (9 सी० सी०) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सर्वश्री जोनसन एंड जोनसन लि०, बम्बई को जारी किये गये लाइसेंस सं० पी०/सी०2064058/डी०/आई०ई० 43/एच०/35-36 सी० जी०/4 दिनांक 30-6-72 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा नियम नियंत्रण प्रति लाइसेंस-धारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या/22(9)/72-73/सी./जो.4]

जे० शंकर, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 15th February, 1974.

S.O. 575.—M/s. Johnson & Johnson Ltd., 30, Forjett Street, Bombay was granted an import licence No. P/C/2064058/D/1E/43/H/35-36/CG. IV dated 30-6-1972 for Rs. 2,72,000 (Rupees two lakhs and seventytwo thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original exchange control purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the total amount for which original Exchange Control Copy was utilized is Rs. 26,727.54 P.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Public, Bombay. I am accordingly satisfied that the original exchange control purposes copy of the said licence has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the power conferred under sub-clause 9(CC) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said Original Exchange Control Purposes copy of import licence No. P/C/2064058/D/IE/43/H/35-36/CG. IV. dated 30-6-72 issued to M/s. Johnson and Johnson Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. 22(9)/72-73/CG. IV]

J. SHANKAR, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली 14 जनवरी 1974

का०आ० 576.—सर्वश्री फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० सिन्दरी को मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत औजारों/उपकरणों का आयात करने के लिए 4,19,830 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० जी०/सी० जी०/2028679/एस० ए० एन०/41/एच/33-34 दिनांक 1-12-71 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। लाइसेंस धारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि उक्त लाइसेंस 2,64,000 रुपये के लिए आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद खो गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी०/सी० जी० 2028679/एस० ए० एन०/41/एच/33-34 दिनांक 1-12-71 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या सी० जी०-2/पी० सी० एम० एम० (112)/71-72]

ए० आर० गोल्डर, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 14th January, 1974

S.O. 576.—M/s. The Fertilizer Corporation of India Ltd., Sindri who were granted import licence No. G/CG/2028679/S/AN/41/H/33-34/dated 1-12-71 for Rs. 4,19,830/- under free foreign exchange for the import of instruments/equipment. They have requested for issue of duplicate copy of the exchange control copy of the licence on the ground that the original exchange control copy has been lost. It has been further reported by the licensee that the said licence was lost after being partly utilised, to the extent of Rs. 2,64,000/-.

In support of their contention the applicant has filled in an affidavit. The undersigned is satisfied that the original exchange control copy of the licence No. G/CG/2028679/S/AN/41/H/33-34/dated 1-12-1971 has been lost and directs that a duplicate exchange control copy of the said licence should be issued to them. The original exchange control copy of the said licence is hereby cancelled.

[No. CG. II/PCMM(112)/71-72]

A. R. GOLDAR, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

का० आ० 577.—सर्वश्री लीडर्स प्रेस प्रा०लि०, 108, सेठ मोती शाह लेन, मेजागांव, बम्बई-10 को 3390/-रुपये (तीन हजार तीन सौ नब्बे मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/आई/3032963/एस/जी एन/47/37-38 दिनांक 7-6-73 (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के बिना) प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क के प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई थी। इस का उपयोग नहीं किया गया था और इसमें 3390 रुपये की पूर्ण धनराशि उपलब्ध है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, महाराष्ट्र राज्य से एक प्रमाणपत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9(सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री लीडर्स प्रेस प्रा० लि०, बम्बई को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी/आई/3032963/एस/जी एन/47/एस/37-38 दिनांक 7-6-73 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एस०-1/67-5/68-69/एन० पी० सी०आई० ए०]

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1974

S.O. 577.—M/s. Leaders Press Pvt. Ltd., 108, Seth Motishah Lane, Mazagoan, Bombay-10, were granted an impost licence No. P/1/3032963/S/GN/47/H/37-38 (without Exchange copy) dated 7-6-73 for Rs. 3390/- (Rupees Three thousand three hundred and ninety only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost. It is further stated that the original Customs Purposes copy was not registered with any Customs authorities at Bank Ltd., It was not utilised and the full amount of Rs. 3390/- is available on it.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Notary Maharashtra State. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended and said original Customs Purposes copy of licence No. P/1/3032963/S/GN/47/37-38 dated 7-6-73 issued to M/s. Leaders Press Pvt. Ltd., Bombay, is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. I.-1/67-V/68-69/NPCIA]

आदेश

का. आ. 578.—सर्वश्री आयल इंडिया लि० 4 इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता को यू० के० से डीजल/गैस इंजन तथा आल्टरनेटर्स के फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये 95,500 रु० के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के एक लाइसेंस सं० पी०/ए० 136996 आर०/एम० एन०/48 एच०/37-38 एम एल दिनांक 10-9-73 स्वीकृत किया गया था। अब उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति उनके द्वारा पारगमन में अस्थानस्थ/खो गई है। विषयाधीन लाइसेंस न तो उपयोग किया गया है और न ही किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराया गया है।

अपने उक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र भेजा है। मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस पी०/ए० 1394996/आर० एम० एन० दिनांक 10-9-73 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदन को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी की जाये। मूल मुद्रा विनियम, नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 11/29/73-74/एम एल-2/2693]

सरदूल सिंह, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 578.—M/s. Oil India Ltd., 4 India Exchange Place, Calcutta-1 were granted licence No. P/A/1396996/R/MN/48/H/37-38/ML-II dated 10-9-73 for the import of spares for Diesel/Gas Engines and Alternators for a C.I.F. value of Rs. 95,500/- from U.K. They have now requested for the issue of Duplicate copy of the Exchange Control Copy on the ground that the original Exchange Control copy of the licence has been misplaced/lost in transit by them. The licence in question has neither been utilised nor registered with any Customs authority.

2. In support of their above said contention the applicants have submitted an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control copy of licence No. P/A/1394996/R/MN/dated 10-9-73 has been lost/misplaced and order that a duplicate Exchange Control copy of the said licence may be issued to the applicant, and that the original Exchange control copy is cancelled.

[File No. 11/29/73-74/ML-II/2693]

SARDUL SINGH Dy. Chief Controller

औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1974

का. आ. 579.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसार नीचे जिस भारतीय मानक के ब्यौरे अनुसूची में दिये गये हैं उसके उपबन्धों में मानक चिन्ह के प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से परीक्षात्मक रूप में एक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय मानक के अनुरूप बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिसूचना तुरन्त ही लागू हो जायेगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक जिसके उपबन्धों में संशोधन किया गया	प्रमाणित वर्तमान खंड की संख्या	भारतीय मानक के उपबन्धों में किये गये संशोधन का विवरण
1	2	3	4
1.	IS: 562-1962 बी एच सी जल विसर्जनीय तेज पाउडर की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	सारणी 1	[सारणी 1, स्तम्भ 2 क्रम संख्या (iii) के सम्मुख]—शब्द "निलम्बनशीलता" के ऊपर तारे का चिन्ह लगाइये और सारणी के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दीजिये:— "*निर्विकारिता :—पदार्थ पर त्वरित भंडारण परीक्षण किये बिना खंड सी० 3.2 में दी पद्धति के अनुसार परीक्षण करने पर उत्पादन की तिथि से छह महीने के अन्त तक पदार्थ की निलम्बन शीलता 45.0 प्रतिशत से कम नहीं पाई जाये। इस कार्य के लिए ई-3.4 में निर्दिष्ट जानकियों के अतिरिक्त एक और जानकी उसी समय ले ली जायेगी और जैसा 3.1 में बताया गया है उसी विधि से बन्द की जायेगी और भंडारण की सामान्य स्थितियों में निर्माता और खरीददार के बीच सहमत स्थान पर रखी जायेगी। इस जानकी का विश्लेषण केवल निलम्बनशीलता देखने के लिये ही किया जायगा, वह भी जब निर्दिष्ट समय के भीतर कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हो कि उसकी निलम्बनशीलता कम हो गई है।"

एम० के० सेन, महानिदेशक

[सं० सी एम डी 13:4]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 14th February, 1974

S. O. 579.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of the Indian Standard, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect :

SCHEDULE

Sl. No. and Title of No. Indian Standard, the Provisions of which have been Modified	Number of the Existing Clause Affected	Particulars of the Modification made to the Provisions of the Indian Standard
1	2	3	4
1. IS : 562-1962 Specification for BHC water dispersible powder concentrates (second revision)	Table 1	[Table 1, col 2 against Sl. No. (iii)]—Put an asterik mark on the word 'suspensibility' and add the following foot note at the end of the table : *Keeping Quality—The material shall retain its suspensibility at not less than 45.0 percent at the end of six months from the date of its manufacture as tested by the method prescribed in C-3.2 without subjecting the material to the accelerated storage test. For this purpose, an additional sample over and above that prescribed in F.3.4 shall be taken at the same time and packed in the identical manner as prescribed in 3.1 and stored at a place as agreed to between the manufacturer and the purchaser, under normal storage conditions. This sample shall be analysed only for suspensibility, in case a complaint is received for loss of suspensibility within the specified time.'

[No. CMD/13:4]

S. K. SEN, Director General

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1974

का.आ. 580.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 की 44) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के कार्यालय में बन्दोबस्त अधिकारी श्री एम० बी० भल्ला को महाराष्ट्र राज्य के लिए उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत प्रबन्ध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों को रोकने के लिए प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 9(16)/सी एण्ड पी०/स्पेशियल सेल/63]

हीरानाथ श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 8th February, 1974

S.O. 580.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954) the Central Government hereby appoints for the State of Maharashtra, Shri M. B. Bhalla, Settlement Officer in the Office of the Regional Settlement Commissioner (Central), New Delhi as Managing Officer for the purupose of performing the functions assigned to such officers by or under the said Act.

[No. 9(16)/C&P/Spl Cell/63]

D. N. ASIJA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1974

का. आ. 581.—यतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड (घ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री एम० के० बी० भटनागर, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को 21 सितम्बर, 1973 से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति का सदस्य पुनः मनोनीत कर दिया है ।

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड (क) का अनुसरण करते हुए असम सरकार ने श्री पी० के० दास, लोक विश्लेषक, असम को 5 जुलाई, 1973 से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति का सदस्य पुनः मनोनीत किया है ।

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) का अनुसरण करते हुए गुजरात राज्य सरकार ने डा० टी० जे० बोमन, कार्य प्रभारी, राजकीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, बड़ौदा को उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति का सदस्य मनोनीत किया है ।

अब अतः अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि श्री एम० के० बी० भटनागर, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय और श्री पी० के० दास, लोक विश्लेषक, असम खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के सदस्य बने रहेंगे और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 1 जून, 1955 की अधिसूचना सं० एम० आर० ओ० 1236 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 22 के सामने प्रथम कालम में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं :

"डा० टी० जे० बोमन,

कार्य प्रभारी

राज्य जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,

बड़ौदा ।"

[सं० पी० 15016/2/73 जनस्वास्थ्य]

ए० एन० गोपालकृष्णन्, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING
(Department of Health)

New Delhi, the 8th February, 1974

S.O. 581.—Whereas in pursuance of clause (d) of sub-section (2) of section 3 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) the Central Government has re-nominated Shri M. K. B. Bhatnagar, Under Secretary, Ministry of Commerce, as a member of the said Committee for a further period of 3 years from the 21st September, 1973.

And whereas in pursuance of clause (e) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, the Government of Assam has re-nominated Shri P. K. Das, Public Analyst, Assam as a member of the said Committee for a further period of 3 years from the 5th July, 1973.

And whereas in pursuance of clause (e) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, the State Government of Gujarat has nominated Dr. T. J. Boman, Officer-in-charge, State Public Health Laboratory, Baroda as a member of the Central Committee for Food Standards representing that Government for a period of 3 years.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Shri M. K. B. Bhatnagar, Under Secretary, Ministry of Commerce, and Shri P. K. Das, public Analyst, Assam shall continue to be members of the Central Committee for Food Standards and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. S. R. O. 1236 dated the 1st June, 1955, namely :—

In the said notification, against item No. 22, for the entries in the first column, the following entries shall be substituted, namely :—

"22. Dr. T. J. Boman, Officer-in-charge,
State Public Health Laboratory,
Baroda."

[No. P. 15016/2/73-P.H.]

A. N. GOPALAKRISHNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1974

का. आ. 582.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 12 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; नामतः

उक्त अनुसूची में, ब्रिटेन से संबंधित प्रविष्टियों में "रायल कालेज आव आबस्टेट्रिसियन्स एण्ड गाइनेकोलोजिस्ट्स, लन्दन" से संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं;

"रायल कालेज आव पैथोलोजिस्ट, लन्दन	एम० आर० सी० (पैथो०)	सदस्य	आर० सी० पी०** (लन्दन)
	एफ० आर० सी० (पैथो०)	फैलो	आर० सी० पी० (लन्दन)"

**बशर्ते कि यह अर्हता किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद प्राप्त की गई हो।

[सं० बी० 11015/15/73 एम०पी०टी०]

New Delhi, the 15th February, 1974

S.O. 582.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 12 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Schedule, in the entries relating to the United Kingdom, after the entry relating to the "Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London", the following entries shall be inserted, namely:—

"Royal College of Pathologists, London	M.R.C. (Path.)	Member	R.C.P.** (Lond.)
	F.R.C. (Path.)	Fellow	R.C.P. (Lond.)"

**Provided this qualification has been awarded after qualifying at an examination.

[V. 11015/15/73 MPT]

आदेश

का. आ. 583.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 28 फरवरी, 1962 की अधिसूचना सं० 16-23/61-चि० I द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए एडिलेड विश्वविद्यालय, दक्षिण आस्ट्रेलिया द्वारा प्रदत्त एम० बी० बी० एस० एक मान्य चिकित्सा अर्हता होगी; और यतः डा० जे० डब्ल्यु० मैकमिलन को जिसके पास उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल माकेश्वर मिशन अस्पताल एसोसिएशन मद्रास के साथ सम्बद्ध है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा :—

(1) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० जे० डब्ल्यु० मैकमिलन उक्त माकेश्वर मिशन अस्पताल एसोसिएशन, मद्रास के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[प० सं० बी० 11016/18/73 एम०पी०टी०]

ORDER

S.O. 583.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-23/61 MI, dated the 28th February, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualifiation, M.B.B.S. granted by the University of Adelaide, South Australia, shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. J. W. Mcmillan, who possesses the said qualification, is for the time being attached to the Sankeshwar Mission Hospital Association, Madras for the purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies:—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Offlcial Gazette, or

(ii) the period during which Dr. J. W. Mcmillian, is attached to the said Sankeshwar Mission Hospital Association, Madras

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/18/73-MPT]

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1974

का० आ० 584.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 31 जनवरी, 1963 की अधिसूचना सं० 16-7/62-चि० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिये यूनिवर्सिटी आव बेसेल, स्विटजरलैंड द्वारा प्रदत्त डाक्टर आव मेडिसिन चिकित्सा, अर्हता, मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० (कुमारी) ई० एम० होक जिसके पास उक्त अर्हता है अध्ययन एवं धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिय फिलहाल एम० एम० एच० एस० हास्पिटल सरकारी मानसिक अस्पताल, श्रीनगर के साथ संबंध हैं।

अतः अब, अक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा—

(1) सरकारी राजपत्र में प्रकाणित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० (कुमारी) ई० एम० होक एम० एच० एस० हास्पिटल एवं मानसिक अस्पताल, श्रीनगर के साथ सम्बन्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि वनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[प० सं० बी० 11016/25/73 एम० पी० टी०]

ORDER

New Delhi, the 18th February, 1974.

S.O. 584.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-7/62 MI, dated the 31st January, 1963, the Central Government has directed that the Medical qualification "Doctor of Medicine" granted by the University of Basal, Switzerland, shall be a recognised medical qualtlication for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Miss) E. M. Hoch, who possesses the said qualification is for the time being attached to the S.M.H.S. Hospital and Government Mental Hospital, Srinagar for the purposes of teaching and charitable work;

Now, therefore in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the offlcial Gazette, or

(ii) the period during which Dr. (Miss) E. M. Hoch is attached to the said S.M.H.S. Hospital and Government Mental Hospital, Srinagar.

which is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 1106/25/73-MPT]

का० आ० 585.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति) नियमावली 1961 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956(1956 का 102)की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार ने डा० वाई० पी० रद्दप्पा, एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० पी० (एडिन) डी० टी० एम० एंड एच० (इंग्लैंड) संयुक्त निदेशक (आयुविज्ञान) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन निदेशालय, बंगलौर को 10 जनवरी, 1974 से डा० एस० ए० कबीर के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1475 दिनांक 13 अप्रैल, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना के "केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 5 के सम्मुख प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाये:—

"डा० वाई० पी० रद्दप्पा, एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० पी० (एडिन), डी० टी० एम० एंड एच० (इंग्लैंड), संयुक्त निदेशक (आयुविज्ञान) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन निदेशालय, बंगलौर"।

[सं० बी० 11019/3/73 एम० पी० टी०]

सती बालकृष्णा, अवर सचिव

S.O. 585.—Whereas the Central Government has, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Medical Council (Post-graduate Medical Education Committee) Rules, 1961, nominated Dr. Y. P. Rudrappa, M.B.,B.S., FRCP(Edin), DTM&H (Eng.). Joint Director (Medical) Directorate of Health and Family Planning Services, Bangalore, to be a member of the Post-graduate Medical Education committee with effect from the 10th January, 1974 vice Dr. S. A. Kabir;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Health) No. S.O. 1475, dated the 13th April, 1970, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated by the Central Government", for the entry against serial No. 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. Y.P. Rudrappa, MBBS, FRCP(Edin), DTM&H (Eg.), Joint Director (Medical), Directorate of Health and Family Planning Services, Bangalore"

[No. 11019/3/73 MPT.]

Km. SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

का० आ० 586.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने गोलाघाट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-4-74 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/74-पी०एच० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 19th February, 1974

S.O. 586.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1st April, 1974 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Golaghat Telephone Exchange, North Eastern Circle.

[No. 5-11/74-PHB]

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1974

का० आ० 587.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बागलकोट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-74 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[सं० 5-9/74-पी०एच०बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

New Delhi, the 23rd February, 1974

S.O. 587.—In pursuance of para (a) of section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director-General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th March,1974 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Bagalkot Telephone Exchange, Karnataka Circle.

[No. 5-9/74-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1974

का०आ० 588.—अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ए० जे० चनचानी, ठेकेदार, बोकारो कोलियरी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० डाकघर बेरमो, जिला गिरिडिह के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स ए० जे० चनचानी, ठेकेदार, बोकारो कोलियरी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, डाकघर बेरमो, जिला गिरिडिह के प्रबन्धतंत्र का श्री मनसुखलाल सी० मनीयार, भण्डारी को 1 जून, 1973 से मैसर्स धोरी कोल सेल्स वर्क्स के प्रतिष्ठान में स्थानान्तरित करना और उसके बाद 21 जून, 1973 से उन्हें काम से रोकना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल०-2012/153/73-एल० आर०-2]

करनैल सिंह, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 1st February, 1974

S.O. 588.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs A. J. Chanchani Contractor, Bokaro Colliery, National Coal Development Corporation Limited, Post Office Bermo, District Giridih and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs A. J. Chanchani, Contractor, Bokaro Colliery, National Coal Development Corporation Limited, Post Office Bermo, District Giridih was justified in transferring Shri Mansukhlal C. Maniar, Store Keeper to the establishment of Messrs Dhori Coal Sales Works from the 1st June, 1973 and thereafter stopping him from work from the 21st June, 1973? If not to what relief is the workman entitled?"

[No. L-2012/153/73-LRII]

New Delhi, the 21st February, 1974

S.O. 589.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Donimalai Iron Ore Project of National Minerals Development Corporation Limited, Post Office Sandur and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th February, 1974.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 84 of 1971

Present :

Sri T. Narsing Rao, M.A., LLB., Industrial Tribunal (Central) Hyderabad.

BETWEEN

Workmen represented by Donimalai Iron Ore Project Employees' Association, Sandur.

AND

Management of Donimalai Iron Ore Project of National Minerals Development Corporation Limited, Post Office, Sandur.

Appearances :

Sri K. Satyanarayana, Advocate—for Workmen.

Sri K. Srinivasamurthy, Director and Hony. Secretary of the Federation of A. P. Chamber of Commerce and Industry for Employers.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) through notification No. L-26011/6/71-LR II dated 25-11-1971, referred the industrial dispute between the Management of Donimalai Iron Ore Project of National Minerals Development Corporation Limited and the Workmen represented by Donimalai Iron Ore Project Employees' Association, Sandur, under Sections 7A and 10(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication by the Tribunal on the following issue :

"Whether the action of the management of Donimalai Iron Ore Project of National Minerals Development Corporation Limited, Post Office Sandur, in dismissing from their services S/Shri Udaya Sahu, Dumper Operator, P. Willaim, Overseer, M. K. Mathai LDC, P.C. Gopalakrishnan, Welder 'B' and G. S. Pillai, U.D.C. with effect from 6th May, 1971 is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 84 of 1971 and notices were directed to both the parties. On behalf of the five dismissed workmen, the President of Donimalai Iron Ore Project Employees' Association filed a claim statement. The allegations of the claims statement briefly stated are these :—The Donimalai Iron Ore Project is an integral part of the National Mineral Development Corporation and a Public Sector undertaking of the Government of India. This project has extensive mineral concessions in respect of large extent of mining area in Sandur Taluq, Bellary-district in Mysore State. The project is started for the purpose of exploiting rich iron-ore deposits at Donimalai and other mining areas in Sandur Taluq. The work was commenced in or about the year 1966 and it undertook "enabling works" like construction of sheds, laying of roads, installation of certain machinery, cutting of benches and prospecting of iron-ore. Nearly 1,200 workers are said to have been employed in this project. A section of workmen, because of their experience are transferred from other projects of the National Mineral Development Corporation to this project. 600 workmen are drafted from the local area as Muster-roll men. Their services are kept as temporary without any justification even though they have completed continuous service of more than one year. Thus the 1,200 workers are said to have comprised of three categories, regular and permanent workers, Muster-roll men and Time-bound workers. Out of them 500 workmen are the Muster-roll men and 200 are the Time bound workers and the remaining are the Regular workmen who have completed three to four years of service at Donimalai. The project is said to be on the top of Donimalai Hill and is a forest area and is at a distance of more than 18 kilometres from Sandur. The transport facilities are said to be meagre and even other facilities are said to be lacking. The workmen therefore organised themselves into a Trade Union under the name and style of Donimalai Iron Ore Project Employees Association. The workmen placed a charter of demands along with the notice of strike dated 22-11-1970. The Assistant Labour Commissioner entered into a conciliation. During the conciliation proceedings the Senior Administrative Officer suggested a bipartite negotiation. The said Administrative Officer under took to arrange such negotiation between the General Manager and the office bearers of the Union within three weeks. The last day of the three weeks period was 9th January, 1971. The General Manager who visited the project on the said date, went away without holding any discussion with the representatives of the Union. One of the major demands in the notice related to regulation of Muster-roll and Time Bound workers who had put in 240 days of continuous service. It is however alleged that the five workmen who stand now dismissed are regular employees, and that their services were regularised long prior to their dismissal. They are also the office bearers of the Trade Union and as such were protected workmen. On 9th January, 1971 when the General Manager left the project without discussion with the Union Leaders the workmen demonstrated at about 6.00 p.m. and resolved to protest against the attitude of the Management in not regularising the Muster-roll and Time-bound workers, and authorised the Executive Committee to take further steps inclusive of taking a decision on 'strike' to achieve their demands. It is alleged that this Trade Union was not even recognised by the Management on account of its anti-labour and anti-Trade Union attitude. The Management is said to have decided hereafter to retrench a large body of Muster-roll men and 200 Time Bound workers with effect from 16-1-1971. This is alleged to be intended to sabotage the Trade Union movement. The workmen therefore demonstrated peacefully on 15-1-1971 after duty hours protesting against this decision of the Management. The Office bearers of the Union request the Management to shelve the retrenchment till the bipartite negotiation agreed to are over. The Senior Administrative Officer is said to have consented to it. Thus the workmen proposed to be retrenched were allowed to resume their duty on 16-1-1971 onwards. On or about 18th January, 1971 the General Manager did not approve the action of the Senior Administrative Officer postponing the implementation of the retrenchment. The Senior Administrative Officer therefore gave a false complaint to the Police against the office bearers of the Union alleging that on 9-1-1971 and 15-1-1971 the office bearers of the Union and other important functionarise indulgeg in violence, had gheroed him and other officers and obtained their undertaking in writing under duress. The Union officials were arrested by the Police. While they were so in the custody 327 Muster-roll workmen and 207 Time Bound workers were retrenched without even giving a notice of termination and without paying the terminal benefits. The Management is thus said to have indulged in unfair labour practice. It is urged that many "enabling works" were yet to be completed by the Management and there was no justification for the retrenchment of the above workmen. The Management thereafter clamped certain restrictions on the workmen. The workmen were asked to vacate their quarters at the Hill top and they were directed to give attendance every day at 9.00 a.m. Many of the workmen are said to have been suspended. Their movements were sought to be regulated under a permit. Thus the project area was converted into a veritable concentration camp, thereby terrorising the workmen not to indulge in any trade union activities. While so, the Management issued show cause notices to these five workmen for indulging in violence on 9-1-1971 and 15-1-1971. The allegations in the show cause notice are said to be false. It is also contended that the charge memos were not issued by the proper authority. The domestic enquiry held by the Board of enquiry consequently is said to be improper, illegal and devoid of authority. The conduct of enquiry was motivated and opposed to the principles of natural justice and was in violation of the model Standing Orders. The Workers Associations however resolved to issue a strike notice on a charter of demands inclusive of the demand to withdraw all disciplinary actions against the office bearers and important functionaries of the Union. A strike notice dated 22-3-1971 was first issued. It was followed by another strike notice dated 30-4-1971. The Assistant Labour Commissioner, Bangalore, entered upon conciliation on 5th May, 1971. While the conciliation proceedings were thus pending, the Management issued dismissal orders regarding the five workmen herein. The order of dismissal is said to be illegal, invalid and void. The Assistant Labour Commissioner to whom the Management made an application for approval, of the dismissal is said to have rejected the same.

3. As regards the affairs of the Canteen and Co-operative Stores run by the Management, the Management is said to have taken a decision to serve plate meal. Sri Mathai and Gopal Krishnan are said to have taken out a demonstration on 1-12-1970 against this decision of the Management. The demonstration is alleged to be a peaceful one but subsequently the Management alleged that the these two persons incited and instigated workmen, and chose to brand this action of the workmen as a misconduct. It is urged that there was no immediate action taken by the Management if these two employees in fact indulged in such disorderly behaviour of inciting the workmen. Thus the charge against these two workmen for the alleged misconduct on 1st December 1970 is said to be false and the very incident of that day is characterised by them as a fiction.

4. The entire domestic enquiry proceedings as against these five workmen are said to be the result of vindictive attitude of the Management. The orders of dismissal are said to be bad in law. The charges framed under the provisions of National Mineral Development Corporation Employees Conduct Rules are said to be bad as the workmen are governed by the Industrial Employment Model Standing Orders. The said charges framed by or under the authority of the General Manager are incompetent. The appropriate authority to frame charges is said to be the Mines Manager. The memorandum of charges did not disclose the names of the witnesses and the nature of the evidence sought to be let in against the workmen. The charge memos are therefore void **ab-initio.** The Chairman of the Enquiry Committee was a witness to the alleged acts of misdemeanour alleged against the workmen. Thus the constitution of the Enquiry Board is itself improver and illegal and violative of principles of natural justice. Inspite of the requisition for the details of the preliminary enquiry, the names of the witnesses are said to have not been furnished to the workmen. The assistance of a representative to conduct the case on behalf of the charged workmen is said to have been dishonestly refused by the Board of Enquiry. The enquiry is characterised some thing like a "star chamber trial". The witnesses for the Management were terrorised and were made to depose against the workmen. Thus these five workmen are said to have been picked and chosen as the victims of the vindictive attitude of the Management. Thus the workmen were not allowed to the Hill top where from they could bring the witnesses. Even the evidence let in by the Management bristles with improbabilities, self-contradictions and does not establish the misconduct alleged against them. The charged workmen were not permitted to examine their defence witnesses. The order of dismissal passed against Sri William is not based on the Standing Orders and therefore it is alleged to be illegal. The Management is said to have terrorised the witnesses to give false evidence and that some workmen have succumbed to the threats and some left the service. Thus the domestic enquiry proceedings are said to be vitiated entirely. In short it is alleged that the action of dismissal taken by the Management against these five workmen was for their Trade Union activities. It is also alleged that these five workmen who are regular workmen had no bad antecedents and that while awarding the punishment, the previous record of the workmen was not taken into consideration. It is alternatively contended that under Section 11A of the Industrial Disputes Act, the Tribunal can also award lesser punishment even if the alleged misconduct stands proved. It is further contended that the Management rushed through the domestic enquiry proceedings without awaiting the result of the prosecution launched by the Police on the basis of complaint made by the Senior Administrative Officer and though the said cases were pending before the Munsif Magistrate, Kudligi. The five workmen thus sought for setting aside their orders of dismissal and for reinstatement with back wages, continuity of service and consequential benefits.

5. In an equally lengthy counter, the Management alleged that the workmen in this project have been enjoying a number of facilities. The minimum basic salary of a monthly paid worker is said to be Rs. 190.00 and inclusive of the allowances, a monthly rated employee is alleged to get Rs. 256.60. Quarters for the workmen are said to be provided with running water facility and electricity and that a number of welfare measures for the workmen have been taken by the Management. A number of prizes are said to have been awarded in the Mine Safety Week and that two Doctors including a lady Doctor are said to be attending to the needs of the workmen. The minimum total emolument of a workmen is said to be double than the what is being paid to a workmen in that region. It is also alleged by the Management that it has recognised a number of Trade Unions and that it is committed to encourage genuine Trade Unions. If the present Union could not be recognised it is because of the reason that this Association has not signed the Code of Discipline which is a **sine quanon** for recognising it under the Industrial Disputes Act. It is alleged that only a few workmen from the other project are transferred to this project and that a substantial majority of the workmen were recruited locally as per its policy. Most of the demands mentioned in the strike notice dated 22-11-1970 are said to have been covered by the terms of reference of Wage Structure Revision Committee constituted by the Corporation and that the same has been settled recently. It is thus denied that elementary facilities were not available for the workmen at the project. It is however conceded these five workmen are regular employees and not Muster-roll or Time Bound workers. During the first conciliation meeting, the suggestion for Bi-partite negotiation is said to have been made by the Labour Commissioner. It is denied that the Senior Administrative Officer undertook to arrange any meeting between the General Manager and the Office bearers of the Union. This aspect is said to have been confirmed by the workmen while they gave evidence in the domestic enquiry. It is alleged that such Bi-partite negotiation could not take place as the office bearers of the Union did not evidence any interest and take the initiative. Though the three weeks time for initiating the negotiation ended on 9-1-1971 it is only on 13-1-1971 the President of the Association sent telegram expressing his willingness for discussion. Even a meeting scheduled to be held on 25-1-1971 could not materialise as the President of the Union did not attend to it. It is denied that a large number of workers were to be terminated from 16-1-1971. Only a few Time-Bound workmen were given notices in terms of their appointment. It is denied that these five dismissed workmen were the protected workmen in as much as the Union was not recognised. It is alleged that on 9-1-1971 these five dismissed workers indulged in organising an unlawful assembly of the workers in front of the Chief Mining Engineers Office on the Hill top. Thus the workmen instigated the crowd to put up road block and wrongfully constrained a number of officers and prevailed upon the Senior Administrative Officer to give an undertaking to the effect that the workmen proposed to be retrenched would be continued till the negotiations are over. It is however reiterated that as the "enabling works" have been completed the retrenchment of those workers were ordered after payment of terminal benefits. However as the incident on 15-1-1971, in which these five workmen indulged in inciting the workmen to violence, was a law and order problem, a complaint was given to the Police and that the Police conducted their investigation. It is denied that while these workmen were in Police custody, 327 workers were retrenched. The number of workmen retrenched is said to be small and the retrenchment was after the payment of the terminal benefit. The Government of India subsequently is said to have declared that the retrenchment was rightly done and that there was no case for referring that issue for adjudication by the Industrial Tribunal. It is denied that the Management clamped all sorts of restrictions on the movement of the Trade Union members or that it chose to pick the office bearers or important functionaries of the Union for disciplinary action. Any regulations imposed are said to be on account of the need for and with regard to the safety of the Mine. The Management also sought to explain the imposition of rent for the quarters on the workmen who were suspended. It is however alleged that with regard to the incident of 9th and 15th of January, 1971 as these five workmen were **prima facie** guilty of misconduct, charge-sheets were issued by competent authority. The enquiry by the Board of enquiry is said to be proper and a legal one and that the enquiry as against these charge sheeted workmen was conducted in an impartial manner and with due regard to the principles of natural justice and in accordance with the procedure under the Model Standing Orders. The charge sheeted workmen have been given full opportunity to participate in the enquiry and also to produce their witnesses. But some of them have not availed the opportunity of producing their defence witnesses. The strike notice including the demand for withdrawal of the enquiry is said to have been issued by the workmen after the enquiry has been completed. The Assistant Labour Commissioner is said to have dropped the proceedings on the application filed by the Management for approval of the dismissal orders. It is also alleged that with regard to Canteen affair, Sri Mathai

and Gopal Krishnan indulged in organising an unlawful assembly on 1-12-1970 and exhorted and incited the workers. Disciplinary proceedings are said to have been instituted against seven persons. Out of them two have pleaded guilty to the charge and tendered their apology. It is alleged that no discrimination is made among the charge sheeted workmen for the alleged misconduct. It is contended that there is no provision of law which requires the names of witnesses or nature of evidence to be shown in the charge memo. The charge memo issued under the authority of the General Manager is said to be valid. It is denied that the Chairman of the Enquiry Board or other members were witnesses to the alleged acts of miscorduct. Thus the constitution of the Enquiry Board is said to be valid and that its members were impartial and unbiased. Thus all other infirmities alleged in the conduct of the domestic enquiry are refuted by the Management. It is further alleged that in view of the grave misconduct being proved the dismissal of the five workmen is justified. The punishment awarded is said to be commensurate with the misconduct committed by the charge sheeted workmen.

6. On behalf of the Workmen, a rejoinder is filed reiterating the allegations of the claims statement. It is not necessary to advert to them in detail.

7. At the stage of enquiry the parties reported a settlement dated 18-1-1974. Under this settlement, the five workmen have received varying amounts ranging from Rs. 14,000.00 and odd to Rs. 8,505.00 and gave up their claim including that of reinsatement and of back wages. Thus the only issue as referred to the Tribunal with regard to the reinstatement with back wages stands settled by the agreement of the parties. That settlement is also signed by Sri A. S. Mallebennur as General Secretary. The same person has signed the claims statement as the President of this Union. The individual workmen who were present have admitted the contents of this settlement. Though there is no provision under the Industrial Disputes Act similar to Order 23 Rule 3 of the Code of Civil Procedure for recording the settlement as such, as a measure of abundant caution, I assertained from the five dismissed workmen about the genuiness of this settlement. They admitted the contents of this settlement and as agreed thereto, the five dismissed workmen received cheques individually for the amounts in my presence. The only point that is left for consideration is whether the settlement is reasonable and fair. It is relevant to note that the issue relates to the dismissal of individual workman. In other words it does not relate to the rights of a body of workmen. When the individual workmen accepted fairly good amounts towards their claim of reinstatement or the consequential back wages and have thus withdrawn their claims, it cannot be said that the settlement is not reasonable or fair. It cannot also be said that the individual workmen have come to accept their respective amounts on account of any undue pressure from the management. It may be that the threat of a prolonged litigation which a workman cannot ordinarily afford might be hanging as a damocles sword over his head but it can equally be said that the sense of practical utility has also prevailed with the workmen. In the circumstances it is held that the settlement is fair and reasonable. There would thus be an award in terms of the settlement.

8. In the result, award is passed accordingly in terms of the settlement. A copy of the settlement be enclosed to this Award.

142 G of I/73—5

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 18th day of January, 1974.

Sd/- Illegible,
INDUSTRIAL TRIBUNAL.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Parties to the disputes :.....

Management

National Mineral Development Corporation Limited, Donimalai Iron Ore Project

Workmen

1. Shri P. Williams
2. Shri Udaya Sahu
3. Shri G. S. Pillai
4. Shri P. G. Gopala krishnan
5. Shri M. K. Mathai

Donimalai Iron Ore Project Employees' Association

Shri A. S. Mallebennur, General Secretary, Donimalai Iron Ore Project Employees' Associations, *representing the above workmen in this dispute.*

Short recital of the case

A dispute has been raised regarding the dismissal from service of five workmen, viz.,

1. Shri P. William
2. Shri Uday Sahu
3. Shri G. S. Pillai
4. Shri P. G. Gopalakrishnan
5. Shri M. L. Mathai

and the same has been referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act. The parties have filed their respective statements of cases before the Tribunal and during the pendency of the Industrial Dispute, parties had prolonged discussions and entered into the following settlement :—

1. The Management agrees to pay—

(1) Shri P. Williams—Rs. 14,415.00
(Rupees Fourteen thousand, four hundred and fifteen only)

(2) Shri Udaya Sahu—Rs. 12,345.00
(Rupees Twelve thousand, three hundred and forty five only)

(3) Shri G. S. Pillai—Rs. 9,765.00
(Rupees Nine thousand, seven hundred and sixty five only)

(4) Shri P. G. Gopalakrishnan—Rs. 8,895.00
(Rupees Eight thousand, eight hundred and ninety five only)

(5) Shri M. K. Mathai—Rs. 8,505.00
(Rupees Eight thousand, five hundred and five only).

2. In consideration of the workmen receiving the amounts stated in clause (1) of the settlement, the workmen hereby give up their claims against the management and it is further agreed that they have no claim whatsoever against the management including that of reinstatement of service.

3. The parties hereby agreed to file the Settlement before the Industrial Tribunal, requesting the Tribunal to pass an Award in terms of the Settlement.

Representing Management :

1. Sd/- (V. S. Kasturi)
Project Manager

2. Donimalai Iron Ore Project.

Representing Workmen :

1. (P. William)
Sd/- 18-1-74

2. (Udaya Sahu)
Sd/- 18-1-74

3. (G. S. Pillai)
Sd/- 18-1-74

4. (P. G. Gopalakrishnan
Sd/- 18-1-74

5. (M. K. Mathai)
Sd/- 18-1-74

Representing Donimalai Iron Ore Project Employees' Association :

Sd/- (A. S. Mallebennur)
General Secretary

Before the Industrial Tribunal Hyderabad.
Hyderabad 18-1-1974.

TRUE COPY

Sd/- Illegible,

Industrial Tribunal.

[No. L-26011/6/71-LR IV.]

S.O. 590.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Orissa Bhubaneswar, the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Messrs Hindustan Steel Limited Rourkela and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th February, 1974.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA : BHUBANESWAR

Present :

Shri I. Mallick, B. L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 1 OF 1973
(Central)
Bhubaneswar, the 31st December, 1973

BETWEEN

The employers in relation to the management of Messrs Hindustan Steel Limited, Rourkela — First Party

AND

Their Workmen. — Second Party

APPEARANCES :

Sri B. B. Rath, Advocate. ... For the first party

Sri A. P. Chatterjee, ... For the Second Party

AWARD

Bar-at-Law

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act) have referred the following schedule of dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Messrs Hindustan Steel Limited, Rourkela, in dismissing the following workmen, employed in their Barsua Iron Ore Mines, Post Office Tensa, is justified ? If not, to what relief, if any, are the workmen entitled ?

1. Shri A. V. Sabhapathy.
2. Shri A. C. Roy.
3. Shri Kanhu Mohanty.
4. Shri Bira Mahakud.
5. Shri D. N. Das.
6. Shri D. Bhagwan Mohanty.
7. Shri S. K. Mukherji.
8. Shri T. Goswami.
9. Shri Fagu Munda.
10. Shri M. Samuel.
11. Shri C. D. Joshi.
12. Shri T. Moharana.
13. Shri K. N. Moharana.
14. Shri K. C. Rout.
15. Shri S. R. Roy.
16. Shri P. Thakur.

2. These 16 dismissed employees (hereinatter referred to as the workmen) were serving in Barsua Mines under M/s. Hindustan Steel Ltd. (hereinafter referred to as the company). Undisputedly, these workmen were convicted for criminal charges under Sections 143 and 448 Indian Penal Code by Sri S. N. Murty, Sub-Divisional Magistrate, Bonai in G. R. Case No. 128 of 1970 by his judgment dated 27-3-72 and sentenced to pay a fine of Rs. 100 each under Sec. 143 I.P.C., in default to undergo simple imprisonment for one week each. No seprate sentence was passed under Sec. 448 I.P.C. The company has dismissed the 16 workmen as per the provisions of clause 32 of the certified standing orders for Mines and Quarries owned by Rourkela Steel Plant of Hindustan Steel Ltd. on the basis of the aforesaid conviction of the workmen. It is also not disputed that the order of conviction passed by Sri S. N. Murty, Sub-Divisional Magistrate, Bonai in G. R. Case No. 128 of 1970 has been set aside by the Additional Sessions Judge, Sundergarh by his judgment dated 19-9-1972 in crl. Appeal No. 27 of 1972 and the workmen have been acquitted of the charges.

3. The case of the workmen, in short, is as follows :—

That the dismissed workmen formed a registered trade union along with others for protection of their legitimate rights and for higher productivity of the industry. That towards May, 1970, at the instance of the authorities, one R. L. Shimant, Assistant, B. I. M. Section, belonging to the rival Union, lodged a false F. I. R. in the Police Station against the dismissed workmen that they, having made an unlawful assembly, committed criminal trespass into his house and abused him in filthy language. The 16 dismissed workmen stood their trial in the Court of the Sub-Divisional Magistrate, Bonai under Sections 143, 448/149 and Section 341 I.P.C. in G. R. Case No. 128 of 1970. The learned Magistrate acquitted the workmen of the charges under Section 149 and 341 I.P.C. and convicted them under Sections 143 and 448 I.P.C. and sentenced to pay a fine of Rs. 100 each under Sec. 143 I.P.C. No separate sentence was passed

under Sec. 148 I.P.C. Being aggrieved by the Judgment and Order dated 27-3-72 passed by the learned Sub-Divisional Magistrate, Bonai, the dismissed workmen preferred Criminal Appeal No. 27 of 1972 in the Court of the learned Additional Sessions Judge, Sundergarh on 26-4-72 and obtained stay for realisation of fine as per the order of the Court dated 29-4-72. During the pendency of the Criminal Appeal No. 27 of 1972 in the Court of the Additional Sessions Judge, Sundergarh, the workmen received orders from the General Manager, Hindustan Steel Ltd. through the Manager, Barsua Mines in the month of August 1972 that as the workmen had been convicted of criminal charges in the court of law under Sections 143 and 448 I.P.C., they were dismissed from service with effect from the date of the issue of the order in accordance with clause 32 of the certified standing orders for Mines and Quarries. The workmen thereupon submitted a representation to the General Manager intimating the fact that Crl. Appeal No. 27 of 1972 had been filed by them.

4. That the Crl. Appeal No. 27 of 1972 was allowed by the Additional District and Sessions Judge by his Judgment and order dated 19-9-72 and the sentence and conviction passed against the workmen were set aside and they were acquitted honourably. That even after the acquittal of the workmen, the company has not reinstated them in service. That the order of dismissal is illegal and unjustified. Further, order No. 32 of the certified standing orders is ultra vires the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946. The workmen, therefore, pray that they should be reinstated in service with back wages from the date of their dismissal.

5. The case of the company, in short, is as follows :—

That at about 5 p.m. on 27-5-70, the workmen along with others formed an unlawful assembly and in furtherance of their common object led a mob of about 60 persons and forcibly trespassed into the residence of Shri R. L. Srivastava, an Assistant in the Office of the Manager, Barsua Iron Mines and abused Sri Srivastava in filthy languages and threatened him with assault. They also prevented him from going to hospital where he was urgently required to go for treatment of his ailing child. The above activities of the workmen within the company's estate amounted to grave and serious misconduct which is detrimental to the industrial peace and harmony. Though the misconduct of the workmen warranted immediate disciplinary action, the management did not draw up any disciplinary proceedings in view of police investigation into the criminal charges. The police submitted a charge-sheet against the workmen and they stood their trial in G. R. Case No. 128 of 1970. The learned Sub-Divisional Magistrate, Bonai convicted the workment under Sections 143 and 448 I.P.C. and sentenced to each of them to pay a fine of Rs. 100 under Sec. 143 I.P.C. in default to undergo simple imprisonment for a period of one week.

6. That the workmen having been convicted by a court of law for criminal charges were liable to be dismissed from service as per the conditions contained in clause 32 of the certified standing orders of the company. That the termination of service of the workmen upon their conviction by a court of law was a termination of service strictly in accordance with the provisions of certified standing orders and a contractual termination and as such, the same is both legal and justified.

7. That the company subsequently learnt that the workmen went on appeal before the District & Sessions Judge, Sundergarh against the Judgment and Order of conviction passed by the learned Sub-Divisional Magistrate, Bonai and in Crl. Appeal No. 27 of 1972, the Judgment order passed by the learned Sub-Divisional Magistrate, Bonai were reversed, although the facts of trespass etc. committed by the workmen were accepted by the learned appellate Court. The State Government have preferred Crl. Appeal No. 50 of 1972 in the Hon'ble High Court which has been admitted and leave granted to appeal against the said judgment. That the subsequent development does not in any way nullify the earlier action taken strictly in accordance with the conditions of service as provided in certified standing orders of the company. In the absence of any provision in the standing orders to the contrary, the action flowing from the provisions of certified standing orders became final and binding and it was improper on the part of the appropriate Government to refer the matter for adjudication basing on the subsequent developments. That for the purpose of the present adjudication, subsequent developments are immaterial. That in the mean time, the workmen moved the Hon'ble High Court of Orissa in O.J.C. Nos. 963 to 977 of 1972 challenging the action of the management in terminating their services. That the reference is otherwise bad in law and is opposed to the very spirit of the Industrial Disputes Act and the Industrial Employment (Standing Orders) Act. On the aforesaid facts, the company contends that the termination of services of the workmen is proper, legal and justified.

8. At the outset, I may state here that Hon'ble High Court of Orissa in Original Jurisdiction Case No. 884 of 1972 have been pleased to hold that certified standing order No 32 is not ultra vires the Central Act. In view of the aforesaid order of the Hon'ble Court, the learned counsel for the workmen has not pressed his point that standing order No. 32 is ultar vires of the Central Act. I, therefore, hold that standing order No. 32 is not ultra vires the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1966.

9. It is vehemently contended by the learned counsel appearing for the workmen that since the Crl. Appeal No. 27 of 1972 was allowed and the order of conviction and sentence passed against the workmen by the learned Sub-Divisional Magistrate, Bonai was set aside, it should be taken that the workmen had not been convicted. He further contends that until the conviction and sentence is final, the workmen should not have been dismissed under order 32 of the standing orders. He, therefore urges that the order dismissal should be quashed as unjustified. In support of his contention he has relied on the decision reported in A.I.R. 1961 Madras 486, A. I. R. 1959 Punjab 410, A.I.R. 1960 Allahabad 538, A.I.R. 1965 Punjab 153 and A.I.R. 1965 Calcutta 75. The learned Legal Adviser of the company relying on the decisions reported in A.I.R. 1964 S. C. 1272, contends that in view of the contractual relationship between the employer and employees, the decisions under Art. 311 of the Constitution cited by the learned counsel for the workmen are not applicable. He further contends that in the interest of balance of convenience, the workmen should not be reinstated till the Crl. Appeal pending in the Hon'ble High Court is disposed of.

10. In the decision reported in A.I.R. 1961 Madras 486, Their Lordships in para 12 of their Judgment have held—

> "Once the conviction is set aside or quashed the dismissal order must fall to the ground. An acquittal of a person of a criminal charge by a higher court setting aside the conviction passed by a subordinate or an inferior court is tantamount to, the person not having been convicted at all. The setting aside of a wrong order of a court results in the position as if such order was never in existence, though as a fact the order was passed and lasted till it was set aside. This view of the matter is not a legal fiction as the proceedings forming the subject matter of a criminal charge against a person from the primary court of trial to the ultimate court of final appeal or revision really constitute one proceeding and however varying the fortunes of the person indicated may be, the proceeding can always have only one result, and that is the result of the last proceeding which becomes indefeasibly final".

Though in the reported case, Their Lordships considered Art. 311 of the Constitution, their view as quoted above is applicable to the present case as well. As in the present case, in the Case reported in A.I.R. 1960 Allahabad 538, the petitioners has been convicted for offences under Sections 409 and 477 I.P.C. by the trial court and they were acquitted of those charges by the appellate court. The orders of dismissal were passed at a time when appeals against the conviction were already pending before the Sessions Judge who ultimately allowed them. Though His Lordship considered the legal implications of Art. 311 of the Constitution, he has been pleased to hold in para 3 of the Judgment that a proceeding will not be said to have led to his conviction if it has not resulted ultimately in conviction

or as a consequence of appeal, has ended in an acquittal. Appeal is a continuation of the proceedings commenced on the criminal charge and it does not conclude in a conviction where an appeal is prefered against the order of the trial Court or of any subsequent Court until these subsequent proceedings have finally ended. There is no conclusion of the proceedings which, therefore, cannot be said to have resulted in a conviction until either the order has become final by efflux of time or has been upheld, where an appeal or revision is preferred, by the higher Court. In the decisions reported in A.I.R. 1965 Punjab 153 and in A.I.R. 1959 Punjab 401, Their Lordships have subscribed to the aforesaid view though they have referred to the legal implications of Art. 311 of the Constitution. In the decision reported in 1965 Cal. 75, His Lordship has also subscribed to the same view. Of course, in the aforesaid decisions the legal implications of Art. 311 were considered, but the fundamental principle is that when conviction by a trial court is set aside in appeal, it should be taken as it there is no conviction at all. The decision cited by the Legal Adviser of the Company proceeds on altogether different context and as such, it is not applicable to the present case.

11. The workmen were convicted of the criminal charges as said above in G. R. Case No. 128 of 1970 on 27-3-72. Vide Ext. B. The Crl. Appeal No. 27 of 1972 was preferred on 26-4-1972 and on 29-4-1972, order was passed granting stay of realisation of fine. Vide Ext. 6. The appellate Court's Judgment is marked Ext. 5 The appeal was allowed, conviction and sentence passed against the workmen were set aside and they were acquitted on 19-9-72. During the pendency of the appeal to the knowledge of the company, the orders of dismissal were passed in August 1972. Vide Exts. C. to S. Having come to know that Crl. Appeal No. 27 of 1972 against the Judgment of the learned Sub-Divisional Magistrate, Bonai had been filed, the authorities of the company should have awaited the result of the appeal. As has been held by Their Lordships in the aforesaid decisions, the conviction should be final either by higher court or by efflux of time, so that the order of dismissal should be passed. Before the order of conviction became final, the orders of dismissal passed by the company were unjust. The view taken by their Lordships in the aforesaid decisions is that if the conviction passed by a trial court is set aside by an appellate court, it should be taken as if there was no conviction at all and in this view of the matter, I hold that the action of the management of Messrs Hindustan Steel Limited, Rourkela, in dismissing the following workmen, employed in their Barsua Iron Ore Mines, Post Office Tensa is not justified and as such, they should be reinstated in service with full back wages.

12. Sri Rath, Legal Adviser of the company contends that in the interest of balance of convenience, the workmen should not be reinstated until the Crl. Appeal pending in the Hon'ble High Court is disposed of. In view of the Judgment of the first appellate Court setting aside the conviction of the workmen, it should be held that they have not been convicted at all. Of course, the appeal against the acquittal filed in the Hon'ble High Court has been admitted. The workmen may face the consequences according to law, but till then they should not be continued to be dismissed employees and kept out of employment.

The reference is answered and award is passed accordingly.

L. MALLICK,
Presiding Officer, Industrial Tribunal,

31-12-1973.

Dictated and corrected by me.
Sd/-
Presiding Officer, Industrial Tribunal.
31-12-73.

[No. L-26011/18/72-LRIV]
KARNAIL SINGH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1974

का. आ. 591—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई० एन० माथुर को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित स्कीम और कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक राज्य से अधिक में विभाग या शाखाएं हैं सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए-12016/3/72-पी० एफ० I]

New Delhi, the 18th February, 1974

S.O. 591.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri I. N. Mathur to be an Inspector for the whole of the Union territory of Delhi for the purposes of the said Act, and the Scheme and the family pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to , or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/3/72-PF. I]

नई दिल्ली, 21 फरवरी 1974

का० आ० 592—यतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री गुलाम हुसैन के स्थान पर श्री अनुपसिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग को नाम निर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में '(धारा 4 के खंड (घ) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट)' शीर्षक के अधीन मद 20 के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री अनूप सिंह,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
श्रम विभाग लखनऊ ।"

[फा०सं० यू-16012(4)/74-एच आई]

New Delhi, 21st February, 1974

S.O. 592.—Whereas the State Government of Uttar Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Anup Singh, Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Labour to represent that State on the Employees' State Insurance, Corporation, in place of Shri Ghulam Hussain ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of

Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the head' (Nominated by the State Governments under clause (d) of section (4); for the entry against item 20, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Anup Singh, Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Labour, Lucknow".

[No. F. U.-16012(4)/74-HI]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1974

का० आ० 593.—यतः कर्नाटक राज्य सरकार ने, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, डी० पी० आर० देसाई के स्थान पर डा० बी० वी० पुट्टराज उर्स, निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवा, कर्नाटक सरकार, को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1947 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3680, तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट "शीर्षक के अन्तर्गत, मद (13) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"डा० बी० वी० पुट्टराज उर्स,
निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन,
कर्नाटक सरकार, बंगलौर"

[फा०सं०यू०-16012(21)/73-एच० आई०]

New Delhi the 22nd February, 1974

S.O. 593.—Whereas the State Government of Karnataka has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Dr. B. V. Puttaraj Urs. Director of Health and Family Planning Services, Government of Karnataka to be a member of the Medical Benefit Council in place of Dr. P. R. Desai.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 3680, dated the 21st August, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10)", for the entry against item (13), the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. B. V. Puttaraj Urs, Director of Health and Family Planning, Government of Karnataka, Bangalore".

[No. F. U-16012(21)/73-HI]

का० आ० 594.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1947 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2763, तारीख 27 मई, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से धारा 4 के खण्ड (छ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे मद 28 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "श्री टी० एन० सिद्धान्त, अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस, 24, कैनिंग लेन, नई दिल्ली-1" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा०सं०यू०-16012/(2)/74-एच० आई०]

S.O. 594.—In pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated by the Central Government under clause (g) of section 4 in consultation with organisation of employees recognised by the Central Government for the purpose", for the entry against item 28, the entry "Shri T. N. Siddanta, Secretary, All-India Trade Union Congress, 24, Canning Lane, New Delhi-1" shall be substituted.

[No. F. U-16012(2)/74-HI]

का० आ० 595—यतः उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948) का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में डा० जे० के० द्विवेदी संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश सरकार को डा० डी० एन० शर्मा के स्थान पर चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिकारी, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम कऔर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. 3680, तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सम्पृक्त राज्य सरकारों द्वारा नाम निर्दिष्ट " शीर्षक के अधीन मद (17) के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

डा०" जे० के० द्विवेदी,
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर"

[फा०सं०यू०-16012(3)/74-एच० आई०]

लालफक जुआला, अवर सचिव

S.O. 595.—Whereas the State Government of Uttar Pradesh has in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Dr. J. K. Dwivedi, Joint Director of Health Services, Government of Uttar Pradesh to be a member of the Medical Benefit Council in place of Dr. D. N. Sharma ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 3680, dated the 21st August, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10)", for the entry against item (17), the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. J. K. Dwivedi, Joint Director of Health Services, Employees' State Insurance Scheme, Government of Uttar Pradesh, Kanpur".

[F. No. U-16012(3)/74-HI]
LALFAK ZUALA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

का० आ० 596.—यत: इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद थिरू जी० गोपीनाथ, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, मद्रास मुख्यालय के समक्ष लम्बित है;

और यत: थिरू जी० गोपीनाथ की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रहीं,

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 33-ब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू टी० पलानियप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा, और थिरू जी० गोपीनाथ से उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त कार्यवाहियों के निपटान के लिए उक्त औद्योगिक अधिकरण, मद्रास को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	पक्षकारों का नाम	अधिसूचना सं० जिसके द्वारा निर्दिष्ट की गई
1.	वर्कमैन बनाम प्रोडक्सन सेन्टर, एट्टूमनूर, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट।	सं० एल 42012/21/73/एल०आर० 3 तारीख 19 दिसम्बर, 1973।

[सं० एल० 42012/21/73-एल० आर० 3]
के० एम० त्रिपाठी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1974

S.O. 596.—Whereas the industrial dispute specified in the schedule hereto annexed is pending before Thiru G. Gopinath, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras;

And, whereas the services of Thiru G. Gopinath have ceased to be available ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru T. Palaniappan as the Presiding Officer, with headquaters at Madras, withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Thiru G. Gopinath and transfers the same to the said Industrial Tribunal, Madras for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of parties	Notification No. by which referred
1.	Workmen Vs. Production Centre, Ettumanur, Kottayam District.	No. L. 42012/21/73/LRIII, dated the 19th December, 1973.

[No. L. 42012/21/73/LRIII]
K. M. TRIPATHI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

का० आ० 597.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स पोथेन जोजफ एण्ड सन्स, एक्सपोर्टर्स एण्ड इम्पोर्टर्स, कोचीन-3 के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पलानियप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स पोथेन जोजफ एंड सन्स, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, कोचीन-3 के प्रबन्धतंत्र की श्री के० डी० जार्ज शिपमेंट टैली क्लर्क को 3 फरवरी, 1973 से नियोजन से इन्कार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल०-35012/4/73-पी० एण्ड डी०]

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1974

S.O. 597.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Pothen Joseph and Sons, Exporters and Importers, Cochin-3 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refer the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Pothen Joseph and Sons, Exporters and Importers, Cochin-3 in denying employment to Shri K. D. George, Shipment Tally Clerk from 3rd February, 1973 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L-35012/4/73-P&D]

आदेश

का० आ० 598.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स थेराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कार्पोरेशन, मोरमुगाओ (गोवा) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मेसर्स थेराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कार्पोरेशन, मोरमुगाओ (गोवा) के प्रबन्धतंत्र की, अपने कर्मकार श्री शेख मोहीदीन, सहायक सेम्पलर को सेवा से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 36012/9/73-पी० एण्ड डी०]

ORDER

S.O. 598.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Therapeutics Chemical Research Corporation, Marmagao (Goa), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Therapeutics Chemical Research Corporation Marmagao (Goa) in dismissing their workman Shri Shaikh Mohidin, Assistant Sampler, from service is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-36012/9/73-P&D]

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1974

का० आ० 599.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में लान्च "एम० एल० रत्ना" वास्को-डे-गामा (गोवा) के स्वामी, श्रीमती जूलियट एस० फरनान्डीज के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या लान्च 'एम० एल० रत्ना' (श्रीमती जूलियट एस० फरनान्डीज) के प्रबन्धतंत्र का श्री नानेश्वर डी० नारवेकर, लान्च खलासी की सेवाओं को समाप्त करना न्यायोचित था ?

यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ?"

[सं० एल० 36012/7/73-पी० एण्ड डी०]

ORDER

S.O. 599.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Shrimati Julieta S. Fernandes, Owner of the Launch "M. L. Ratna" Vasco-da-Gama (Goa), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of the Launch "M. L. Ratna" (Shrimati Julieta S. Fernandes) was jujstified in terminating the services of Shri Naneshwar D. Narveker, Launch Khalasi ?

If not, to what relief is the workman entitled and from what date ?"

[No. L-36012/7/73-P&D]

आदेश

का० आ० 600.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में लान्च "सागर" वास्को-डे-गामा (गोवा) के स्वामी श्री बी० डी० नायक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या लान्च 'सागर' के स्वामी श्री बी० डी० नायक का श्री ए० एम० पराडकर, लान्च खलासी की सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित था ?

यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ?"

[सं० एल० 36012/8/73-पी० एण्ड डी०]

बी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

ORDER

S.O. 600.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Shri B. D. Naik-

Owner of the Launch "Sagar" Vasco-da-Gama (Goa), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether Shri B. D. Naik, Owner of the Launch "Sagar" was justified in terminating the services of Shri A. M. Paradkar, Launch Khalasi ? If not, to what relief is the workman entitled and from what date?"

[No. L-36012/8/73-P&D]
V. Sankaralingam, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1974

का० आ० 601.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिम्सन एण्ड मेक्कोनची (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 18, सिडेनहैमस रोड, मद्रास-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(36)/73-पी० एफ०-2(i)]

New Delhi, the 18th February, 1974

S.O. 601.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Simson & McConechy (India) Private Limited, 18 Sydenhams Road, Madras-3, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1973.

[No. S. 35019/36/73-PF. II(i)]

का० आ० 602.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1973 से मैसर्स सिम्सन एण्ड मैक्कोनची (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 18, सिडेनहैमस रोड, मद्रास-3 को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(36)/73-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 602.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the 1st March, 1973, the establishment known as Messrs Simson & McConechy (India) Private Limited, 18, Sydenhams Road, Madras-3 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/36/73-PF. II(ii)]

का० आ० 603.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लोहा भवन बिजनेस् एण्ड आफिस प्रेमिसेज्, कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लोहा भवन पी० डी० मेलो रोड, मुम्बई-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018(105)/73-पी० एफ०-2]

S.O. 603.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Loha Bhavan Business and Office Premises Co-operative Society Limited Loha Bhavan P. D'Mello Road, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1973.

[No. S. 35018/105/73-PF. II]

का० आ० 604.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स सिफूड लिमिटेड, मधुपटना, जिला कटक (उड़ीसा) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(116)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 604.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cifoods Limited, Madhupatana, District Cuttack (Orissa), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1972.

[No. S. 35019/116/73-PF. II]

का० आ० 605.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राधाकृष्ण मेटल रोलिंग मिल्स, चिलाकालापुडी, मछलीपतनम, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(104)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 605.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Radhakrishna Metal Rolling Mills, Chilakalapudi, Machilipatnam, (A.P.) have agreed that the provisions of the Empolyees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1973.

[No. S. 35019/104/73-PF. II]

का० आ० 606.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चन्द्र प्रोसेस संख्या 45, थट्टुमेट्टु स्ट्रीट, शिवकासी डा० धर, रामनाद जिला (तमिलनाडु) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिनियम 1973 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(148)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 606.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chandra Process, No. 45, Thattumettu Street, Sivakashi, P.O. Ramanad District (Tamil Nadu) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1973.

[No. S. 35019/148/73-PF. II]

का० आ० 607.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुकरिस कोलम्बो स्टोर्स, 88 कर्नक रोड, दादाभाई बिल्डिंग, मुम्बई-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018(98)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 607.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sukris Colombo Stores, 88 Carnac Road, Dadabhai Building, Bombay-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1973.

[No. S. 35018/98/73-PF. II]

का०आ० 608.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुदर्शन प्रोसेस, 8-4-169, मुण्डगा नादर स्ट्रीट, शिवकाशी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(17)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 608.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sudarshan Process, 8-4-169 Mundaga Nadar Street, Sivakashi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and the Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1972.

[No. S. 35019/17/73-PF. II]

का० आ० 609—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दूरवाणी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 11, दयावसन्द्रा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, महादेवपुरा, बंगलौर-2, जिसमें (i) 17/2, कनिंघम रोड, बंगलोर, (ii) सं० 24, दरियागंज, दिल्ली, स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स एस-35019(158)/73-पी.एफ.2(i)]

S.O. 609.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dooravani Cables Private Limited, 11 Dyavasandra Industrial Estate, Mahadevapura, Bangalore-2 including its Branches at (i) 17/2 Cunningham Road, Bangalore (ii) No. 24 Daryaganj, Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1972.

[No. S. 35019/158/73-PF. II(i)]

का०आ० 610—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1972 से मेसर्स दूरवाणी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 11, दयावसन्द्रा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, महादेवपुरा, बंगलोर-2 जिसमें (i) 17/2, कनिंघम रोड, बंगलोर, (ii) संख्या 24, दरियागंज, दिल्ली स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(158)/73-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 610.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st October, 1972 the establishment known as Messrs Dooravani Cables Private Limited, 11, Dyavasandra Industrial Estate Mahadevapura Bangalore-2 including its branches at (i) 17/2, Cunningham Road, Bangalore and (ii) No. 24 Daryaganj Delhi for the purpose of the said Proviso.

[No. S. 35019/158/73-PF.II(ii)]

का० आ० 611.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बिल्लेट रीरोलर्स कमिटी 225सी०, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स. एस-35017(64)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 611.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Billet Rerollers Committee, 225C, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-20 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1972.

[No. S. 35017/64/73-PF. II]

का० आ० 612.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नू मेटलाय कास्टिंग वर्क्स, 45/1, बी० एल० शाह रोड, कलकत्ता-53 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(66)/73-पी० एफ०-2]

S.O. 612.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Nu Metalloy Casting works 45/1, B. L. Saha Road, Calcutta-53 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby appeals the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtyfirst day of March, 1972.

[No. S. 35017/66/73-PF. II]

का० आ० 613—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डस्ट्रीयल इंजिनियरिंग स्टोर्स, 10/3, जेरियन रोड (अवनाशी रोड,) पोस्ट बाक्स संख्या 964, कोयम्बटूर-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1592 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35019(131)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 613.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Industrial Engineering Stores, 10/3, Cherian Road (Avanashi Road,) Post Box No. 964, Coimbatore-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pensions Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made-applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1973.

[No. S. 35019/131/73-PF. III]

का० आ० 614.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 49/1, गरियाहट रोड, कलकत्ता-19 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गयी है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(57)/73-पी० एफ० 2)(i)]

S.O. 614.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the mapority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electrical Industrial Distributors, 49/1, Gariahat Road, Calcutta-19 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1971.

[No. S-35017/57/73-PF. II(i)]

का० आ० 615.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1971 से मेसर्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 49/1, मरियाहट रोड, कलकत्ता-19 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017(57)/73-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 615.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st December, 1971 the establishment known as Messrs Electrical Industrial Distributors, 49/1 Gariahat Road, Calcutta-19 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/57/73-PF. II(ii)]

का० आ० 616.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स-दि हैदराबाद वेस्ट कोआपरेटिव मौण्ड मार्गेज बैंक लिमिटेड, म० सं० 3-2/23, मोसिन मंजिल, निम्बोलि अड्डा, काचीगुड़ा, हैदराबाद-27 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(70)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 616.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Hyderabad West Co-operative Land Mortgage Bank Limited H. No. 3-2/23 Mosin Manzil, Nimboliadda, Kachiguda, Hyderabad-27 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1973.

[No. S. 35019/70/73-PF. II]

का० आ० 617.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजेन्द्र फ्लोर्स, 13/1-ए, चेटला रोड, कलकत्ता-27 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं एम-35017(62)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 617.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajendra Floors, 13/1A Chetla Road, Calcutta-27 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1972.

[No. S. 35017/62/73-PF. II]

का. आ. 618.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कलकत्ता मोटर इंजिनियरिंग, 10, डफर स्ट्रीट, डाकघर, लिलुआ, हावड़ा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(67)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 618.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Calcutta Motor Engineering, 10, Duffer Street, P. O., Liluah, Howrah have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1972.

[No. S. 35017/67/73-PF. II]

का. आ. 619.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बंगाल सेफ् एन्ड स्टील वर्कस (प्राइवेट) लिमिटेड, 208, बी० टी० रोड, कलकत्ता 36 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध को उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35017(60)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 619.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bengal Safe and Steel Works (Private) Limited, 208 B.T. Road Calcutta-36 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1971.

[No. S. 35017/60/73-PF. II]

का. आ. 620.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिगफिल प्राइवेट लिमिटेड, पो० बा० 2780, 151 माउंट रोड, मद्रास-2, जिसमें 2/1, तुमकर रोड, यशवंतपुर, बंगलोर-2 स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(109)/73-पी०एफ०2(1)]

S.O. 620.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cigfil Private Limited, P. B. 2780, 151, Mount Road, Madras-2 including its Factory at 2/1, Tunkur Road, Yeswantpur, Bangalore-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1973.

[No. S. 35019/109/73-PF. II(i)]

का. आ. 621.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1973 से मैसर्स सिगफिल प्राइवेट लिमिटेड, पो० बा० 2780, 151, माउंट रोड, मद्रास-2 जिसमें 2/1, तुमकर रोड, यशवन्तपुर बंगलौर-2 स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है नामक स्थापन की उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35019(109)/73-पी०एफ०2(ii)]

S.O. 621.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section of 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st May, 1973, the establishment known as Messrs Cigfil (Private) Limited, P.B. 2780, 151 Mount Road, Madres-2, including its Factory at 2/1, Tumkur Road, Yeswantpur Bangalore-2 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/109/73-PF. II(ii)]

का. आ. 622.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओरिएण्ट इन्जीनियरिंग कम्पनी, 4/1/3 रूसा रोड साउथ फर्स्ट लेन दिगम्बरी-तलला/टालीगंज, कलकत्ता-33 नामक स्थापन संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अगस्त के एकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(63)/73-पी०एफ०2]

S.O. 622.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Orient Engineering Company, 4/1/3 Russa Road, 1st Lane, Digamba Company, 4/1/3 Russa Road, South 1st Lane, Digambaritalla ritalla Tollygunge Calcutta-33 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1971.

[No. S. 35017/63/73-PF. II]

का. आ. 623.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिम्प्लेक्स आटो इंडस्ट्रीज, सिम्प्लेक्स एस्टेट, नागपुर रोड, जबलपुर मध्यप्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी की प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(145)/73-पी०एफ2(i)]

S.O. 623.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Simplex Auto Industries, Simplex Estate, Nagpur Road, Jabalpur M.P. have agreed that the provisions of the Employees' provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S. 35019/145/73-PF. II(i)]

का. आ. 624.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1973 से मैसर्स सिम्प्लेक्स आटो इंडस्ट्रीज, सिम्प्लेक्स एस्टेट, नागपुर रोड, जबलपुर मध्य प्रदेश नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019(145)/73-पी०एफ०2(ii)]

S.O. 624.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st January, 1973 the establishment known as Messrs Simplex Auto Industries, Simplex Estate, Nagpur Road, Jabalpur M.P. for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/145/73-PF. II(ii)]

का. आ. 625.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिन्हाको प्राडक्टस्, 14/2 चाइना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के एकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(65)/73-पी०एफ०2]

S.O. 625.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sinhako Products, 14/2 Old China Bazar Street, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1972.

[No. S. 35017/65/73-PF. II]

का. आ. 626.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एसोसिएटिड ट्रेडिंग कम्पनी, ज्यूज स्ट्रीट, अर्नाकुलम, कोचीन-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की फरवरी के अट्ठाईसवें दिन को प्रवृत्त होगी।

[सं. एस-35019(138)/73-पी०एफ०2]

S.O. 626.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Associated Trading Company, Jews Street, Ernakulam-Cochin, II have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the twenty-eighth day of February, 1974.

[No. S. 35019/45/73-PF. II]

का. आ. 627.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोमथा काम्बाइन्स, 11/4, दिवान बहादुर रोड़, आर० एस० पुरम कोयम्बटूर-2 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019/45/73-पी०एफ० 2]

S.O. 627.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gomatha Combines 11/14, Diwan Bahadur Road, R. S. Puram, Coimbatore-2 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1973.

[No. S. 35019/45/73-PF. II]

का. आ. 628.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि मैसर्स इन्डोक्वप पेस्ट कन्ट्रोल, 2, ओल्ड कोर्ट हाउस कार्नर, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अक्टूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त होगी ।

[सं० एस-35017(59)/73 पी०एफ० 2]

S.O. 628.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indequip Pest Control, 2, Old Court House, Corner, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1972.

[No. S. 35017/59/73-PF. II]

का. आ. 629.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तिरुकोयलूर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, 9, मार्केट स्ट्रीट तिरुकोयलूर, दक्षिण आर्काट जिला नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब, पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।]

[सं. एफ-35019(129)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 629.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tirukoilur Cooperative Urban Bank Limited, 9 Market Street Tirukoilur, S. Arcot District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1973.

[No. S. 35019/129/73-PF. II]

का. आ. 630.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जन मोटर लान्च ट्रांसपोर्टेशन कम्पनी, 113, एकडलिया रोड़, कलकत्ता-19 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35017(53)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 630.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jana Motor Launch Transportation Company, 113 Ekdalia Road, Calcutta-19 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds, and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1970.

[No. S. 35017/53/73-PF. II]

का. आ. 631.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोंकण केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2-एफ, कोर्ट चैम्बर्स, 35-ए, न्यू मेरीन लाइन्स, मुम्बई-20, जिसमें इसका एफ-2, एम० आई० टी० सी० इण्डस्ट्रियल एरिया, बदलापुर, जिला थाना, महाराष्ट्र राज्य स्थित कारखाना भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एम-35018/50/73-पी० एफ० 2]

S.O. 631.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs KONKAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED, 2-F, Court Chambers, 35-A, New Marine Lines, Bombay-20 including its factory at F-2, M.I.D.C. Industrial Area, Badlapur, District-Thana, Maharashtra States have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of August, 1972.

[No. S. 35018(50)/73-PF. II

का. आ. 632.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अविकार फर्नीशर्स 46, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-12 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35017/56/73-पी० एफ० 2]

S.O. 632.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Avikar Furnishers, 46, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1970.

[No. S. 35017(56)/73-PF. II]

का. आ. 633.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान फैब्रीकेशन कम्पनी, डाकखाना पनगर बाजार जी० टी० रोड, जिला बर्दवान नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस०-35017/54/73-पी एफ 2]

S.O. 633.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Hindustan Fabrication Company, Post Office Panagar Bazar, G.T. Road, District Burdwan has agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1972.

[No. S. 35017(54)/73-PF. II]

का. आ. 634.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामदयाल सोमानी एण्ड कंपनी, 158/164, कल्बादेवी रोड, मुम्बई-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के जुलाई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एफ-35018(77)/73-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 634.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bamdayal Somani and Company. 158/164 Kalbadevi Road, Bombay-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1972.

[No. S. 35018/77/73-PF. II(i)]

का. आ. 635.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात मैसर्स रामदयाल सोमानी एण्ड कंपनी, 158/164, कल्बादेवी रोड, मुम्बई-2 नामक स्थापन को 31 जुलाई, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस-35018(77)/73-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 635.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st July, 1972 the establishment known as Messrs Ramdayal Somani and Company, 158/164 Kalbadevi Road, Bombay-2 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/77/73-PF. II(ii)]

का. आ. 636.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे० के० टाइलस्, 381, प्रिंस अनवर शाह रोड, कलकत्ता-31 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35017(55)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 636.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jay Key Tiles, 381, Prince Anwar Shah Road, Calcutta-31 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1972.

[No. S. 35017/55/73-PF. II]

का. आ. 637.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओमको कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, चिटाभाई पटेल रोड, कंडिवली, मुम्बई-67 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 की जुलाई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35018(57)/73-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 637.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Omco Carbon Private Limited, Chitabhai Patel Road, Kandiwli Bombay-67 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1972.

[No. S. 35018/57/73-PF. II(i)]

का. आ. 638.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात मैसर्स ओमको कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, चिटाभाई पटेल रोड, कंडिवली, मुम्बई-67 नामक स्थापन को 1972 की जुलाई के इकतीसवें दिन से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस-35018(57)/73-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 638.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matters, hereby specifies with effect from the 31st day of July, 1972 the establishment known as Messrs Omco Carbon Private Limited, Chitabhai Patel Road, Kandiwli Bombay-67 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/57/73-PF. II(ii)]

का. आ. 639.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामसंस इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) जगाधरी रोड, जगाधरी, हरियाणा राज्य नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35019(157)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 639.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ram Sons Industries (India) Jagadhri Road, Jagadhri, Haryana State have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1973.

[No. S. 35019/157/73-PF. II]

का. आ. 640.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामप्रीत शॉ एण्ड कम्पनी 262, बी० टी० रोड, सुकचार, 24 परगना, पश्चिमी बंगाल नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35017(58)/73-पी० एफ० 2]

S.O. 640.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Ramprit Shaw and Company, 262, B.T. Road, Sukchar 24 parganas, West Bengal have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1971.

[No. S. 35017/58/73-PF. II]

का. आ. 641.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बेकन इण्डस्ट्रियल इलक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवराम इण्डस्ट्रियल एस्टेट, ब्लाक संख्या ए-13, प्रथम मंजिल अम्बेडकर रोड, बम्बई-31 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस० 35018(75)/73-पी० एफ० 2]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

S.O. 641.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Beacon Industrial Electronics Private Limited, Shiv Ram Industrial Estate, Block No. A-13, Ist Floor, Ambedkar Road, Bombay-31 have agred that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S. 35018/75/73-PF. II]

DALJIT SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1974